संयम ◆संस्कार ◆संतुलन

R.N.I. No.-UPHIN/2004/22466

वर्ष-23 अंक- 71
पृष्ठ 8
शनिवार
28 नवम्बर 2026
प्रातः संस्करण
हिन्दी दैनिक
प्रयागराज
मूल्य-1.00

शहर समता

प्रयागराज से प्रकाशित Email : shaharsamta@gmail.com Website : https://Shaharsamta.com

सम्पादक-उमेश चन्द्र श्रीवास्तव

विविध- टमाटर का ताजापन कभी...

विचार- मुट्ठी में दुनिया और छूटता हाथ!

खेल- जसप्रीत बुमराह दोनों टीमों के बीच...

9.70 लाख युवाओं को नौकरी

योगी ने सपा पर साधा निशाना, अगले सप्ताह 50 हजार नियुक्तियां

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी समाजवादी पार्टी (सपा) पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को दावा किया कि उनकी सरकार जिस तेजी से नियुक्ति पत्र बांट रही है, उसकी गति सैफई सिंडिकेट गिन भी नहीं पाएगा। उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि उसे नोट गिनने के अलावा कुछ और गिनना आता ही नहीं है। योगी ने कहा कि अब तक प्रदेश के 9.70 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। यह संख्या सपा के चार और बसपा के तीन कार्यकाल की कुल भर्तियों से दोगुने से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह आठ हजार लेखपाल, 42 हजार होमगार्ड और शिक्षा आयोग के दो हजार चयनित अभ्यर्थियों सहित करीब 50 हजार युवाओं



को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 1,594 लेखा परीक्षकों और सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद संबोधित कर रहे थे। इनमें 201 लेखा परीक्षक और 1,393 सहायक लेखाकार शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी। नौकरी का विज्ञापन निकलते ही चाचा–भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र कोई मुन्ना भाई लेकर चला जाता था। योगी का चाचा–भतीजे का संदर्भ परोक्ष रूप से सपा नेता शिवपाल यादव और उनके भतीजे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर था। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2015–16 में हाईस्कूल, इंटर और स्नातक में तृतीय श्रेणी पाने वाले अभ्यर्थी को लोक सेवा आयोग की परीक्षा में एसडीएम का टॉपर बना दिया गया। आज बिना सिफारिश और लेन–देन के मेधा के आधार पर युवाओं को नियुक्ति मिल रही है। लखीमपुर खीरी के चंदन चौकी के थारू जनजाति के युवा से लेकर रायबरेली, जौनपुर, शाहजहांपुर, गोरखपुर और लखनऊ के सामान्य परिवारों के अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल रहा है। मेधा का अपमान महापाप है और नियुक्ति पत्र युवाओं के परिश्रम का सम्मान है। नवनियुक्त लेखा परीक्षकों और सहायक लेखाकारों को वित्तीय शुचिता की सीख देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी वरिष्ठ अधिकारी या सरकार के दबाव में गलत फाइल पर हस्ताक्षर न करें। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में 167 करोड़ रुपये के बजट वाले गोमती रिवरफ्रंट पर 1,400 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए, फिर भी परियोजना अधूरी रही। मौखिक आदेशों के कारण निचले स्तर के कर्मचारी जेल गए, जबकि जनता का पैसा लूटकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति बनाने वाले लोग ऐश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन को लेकर सपा के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्ष 2005 में सपा सरकार ने ही नयी पेंशन योजना लागू की थी, लेकिन 2017 तक कर्मचारियों के खाते नहीं खोले गए और न ही सरकारी अंशदान जमा किया गया। वर्तमान सरकार ने कमेटी गठित कर खाते खुलवाए, सरकारी अंशदान 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया और बजट से 10 हजार करोड़ रुपये देकर 14 लाख कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया।

मंत्रिमंडल ने परिसीमन संशोधन विधेयक को दी मंजूरी



नयी दिल्ली, एजेंसी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने परिसीमन संशोधन विधेयक और इससे संबंधित महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सेवा तीर्थ में हुई बैठक में इन विधेयकों को मंजूरी दी गई। यह माना जा रहा है कि सरकार इन विधेयकों को 30 नवम्बर से बुलाई गई संसद की बैठक में पेश करने वाली है। परिसीमन विधेयक में सभी राज्यों में अनुपात के आधार पर लोकसभा में सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढाने का प्रस्ताव है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में सीटों की यह संख्या अगले 25 वर्षों तक फ्रीज रहेगी। परिसीमन विधेयक के आधार पर ही लोकसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि बैठक में सरकार सदन की स्वीकृति के लिए अति महत्वपूर्ण कामकाज लायेगी। उन्होंने सभी सांसदों से चर्चा में गंभीरता से भाग लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर और एक दिसंबर को लोकसभा में बहुत ही महत्वपूर्ण शबिजनेसश लाया जायेगा और उसे ही दो और तीन दिसंबर को राज्यसभा में पेश किया जायेगा। उन्होंने इस संबंध में किसी विधेयक का नाम नहीं लिया और कहा कि कामकाज क्या होगा इसकी जानकारी उचित समय पर दे दी जायेगी। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय ने संसद की इस बैठक को मानसून सत्र का दूसरा भाग बताया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और 13 अगस्त को दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं किया गया था।

नदियों में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्तः राजस्थान सरकार को लगाई फटकार, अफसरों को भी चेताया

नई दिल्ली, एजेंसी। राजस्थान में जोजरी, बांडी और लूनी नदियों के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सरकार के रवैये को बेहद सुस्त बताया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिकारी इस मामले में कुछ करना ही नहीं चाहते। अगर सरकार और उसके अधिकारी नहीं जागे तो अदालत को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर अधिकारियों के खिलाफ



स्वतरू संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने राजस्थान सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि वह सरकार को सलाह दें कि अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहें, बल्कि जमीन पर उतरकर काम करें। अदालत ने साफ–साफ कहा कि वह लालफीताशाही और नौकरशाही की अड़चनों के कारण इस मामले को आगे नहीं बढ़ने देगी। सुनवाई के दौरान पीठ ने राज्य सरकार की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिकारियों को जगाने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं। अगर उन्होंने समय रहते काम नहीं किया तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। पीठ ने यह भी कहा कि इसका असर केवल संबंधित अधिकारियों पर नहीं, बल्कि पूरी सरकार पर पड़ेगा।

हिन्द महासागर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना जरूरी : जयशंकर

नयी दिल्ली, एजेंसी विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के सदस्य देशों से कहा है कि हिन्द महासागर क्षेत्र को शांतिपूर्ण, स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना जरूरी है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि आईओआरए की 25वीं मंत्रिपरिषद की यहां भारत की अध्यक्षता में हो रही बैठक के उद्घाटन संबोधन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि हिन्द महासागर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, संपर्क और आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र विविधताओं और अवसरों के साथ कई साझा चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। ऐसे में इसे विकास के अनुकूल बनाए रखना सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आईओआरए में भारत की भूमिका और अध्यक्षता का मार्गदर्शन श्महासागरश की सोच से होगा। इसका अर्थ है विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए साझा और समग्र प्रगति। यह भारत की पहले की श्सागरश सोच पर आधारित है, जिसका अर्थ क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा



और विकास है। डॉ. जयशंकर ने बताया कि भारत की अध्यक्षता में इस बार का विषय श हिन्द महासागर क्षेत्र में नवाचार, खुलापन, मजबूती और बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमताश रखा गया है। इसके तहत आईओआरए के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और साझा मुद्दों पर सहयोग मजबूत करने, संवाद साझेदारों के साथ जुड़ाव बढ़ाने, क्षेत्रीय पहलों को बढ़ावा देने और संगठन की वित्तीय व संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक व्यवस्था और भू–राजनीतिक परिस्थितियों के बीच आईओआरए की सामूहिक आवाज को मजबूत करना जरूरी है।

बैठक का विषय श्मजबूत क्षेत्रीय आवाज रू बदलती वैश्विक व्यवस्था में आईओआरए की भूमिकाश इसी जरूरत को दर्शाता है। इसके लिए सदस्य देशों के बीच बेहतर तालमेल, संवाद साझेदारों के साथ सार्थक सहयोग और व्यावहारिक पहलों पर ध्यान देना होगा।

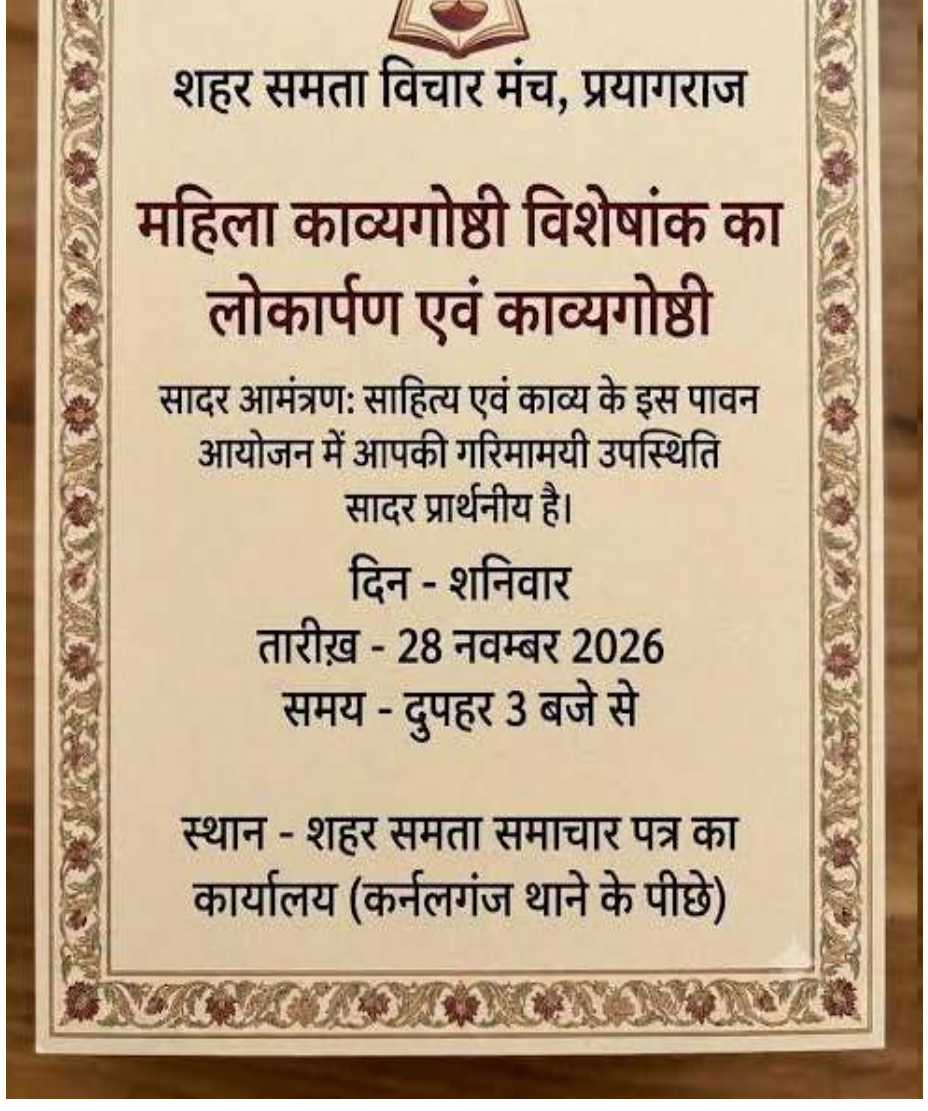

PRESS
हमेशा आपके साथ

दैनिक एवं साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र

शहर समता
संयम ★ संस्कार ★ संतुलन

Website
www.shaharsamta.com

Subscribe on YouTube
youtube.com/@shaharsamtanews

सही खबर, सही समय पर

स्थापित 2001 • RNI Dainik UPHIN/2004/22466 • साप्ताहिक UPHIN/2001/03996 • कार्यालय 289/238 A कर्नलगंज प्रयागराज • संपर्क 9005239332, 9450482227

मोहित अग्रवाल बनाए गए प्रयागराज के नए पुलिस कमिश्नर, पहले रह चुके है एसएसपी

प्रयागराज। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया का तबादला हो गया है। उनके स्थान पर मोहित अग्रवाल को प्रयागराज का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। मोहित पहले प्रयागराज के एसएसपी रह चुके हैं। प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में भी



बदलाव किया गया है। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को प्रयागराज का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है। वहीं, प्रयागराज के पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया को अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना), उत्तर प्रदेश लखनऊ भेजा गया है।

तबादला सूची के अनुसार, प्रयागराज में तैनात पुलिस उपायुक्त कुलदीप सिंह गुनावत को कानपुर नगर भेजा गया है। उनकी जगह कानपुर नगर में तैनात पुलिस उपायुक्त दिनेश त्रिपाठी को प्रयागराज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा प्रयागराज की 42वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक और जेल प्रशासन एवं सुधार सेवाओं के अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे राजेश कुमार श्रीवास्तव को पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ भेजा गया है। इस फेरबदल में प्रयागराज से तीन अधिकारियों का तबादला हुआ है, जबकि दो अधिकारी यहां नई जिम्मेदारी संभालने आएंगे। नए पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त की तैनाती से कमिश्नरेट की कार्यप्रणाली में बदलाव देखने को मिलेगा। पीयूष मोर्डिया ने इसी साल 30 जुलाई को प्रयागराज पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाला था। इस लिहाज से वह करीब चार महीने यहां पुलिस आयुक्त रहे।

टीजीटी भर्ती: एकल विषय डिग्री वालों को आवेदन की अनुमति, यूपीईएसएससी ने लिया अहम फैसला

प्रयागराज। एडेड कॉलेजों में सहायक अध्यापक (टीजीटी) भर्ती के लिए उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन का मौका मिलेगा, जिन्होंने स्नातक के बाद किसी एक विषय में दो वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम पूरा किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ऐसे अभ्यर्थियों को अनंतिम रूप से आवेदन की अनुमति दे दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 नवंबर निर्धारित है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बृहस्पतिवार को एडेड कॉलेजों में सहायक अध्यापक (टीजीटी) भर्ती के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयोग ने स्नातक के बाद एकल विषय में दो वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अनंतिम रूप से आवेदन करने की अनुमति दी है। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया जा रहा है। अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन पूरी तरह अनंतिम रहेगा, जो संबंधित अंकपत्रों, प्रमाण पत्रों और अन्य शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन पर निर्भर करेगा। आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एकल विषय में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि का डिग्री पाठ्यक्रम पूरा किया है, वे पात्र होंगे।

इस डिग्री पाठ्यक्रम को स्नातक डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही, अभ्यर्थियों ने स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50 फीसदी या स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 45 फीसदी अंक प्राप्त किए हों। ऐसे सभी अर्ह अभ्यर्थी जो ये शैक्षिक अर्हताएं पूर्ण करते हैं, वे अंतिम तिथि 28 नवंबर तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बहस पूरी होने के बाद अतिरिक्त गवाही के लिए ठोस कारण बताना जरूरी: हाईकोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब पक्षकार को गवाह पेश करने का पूरा अवसर मिला हो और उसने खुद अपना साक्ष्य बंद करा दिया हो तो बाद में अतिरिक्त गवाही की मांग के लिए ठोस कारण बताना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब पक्षकार को गवाह पेश करने का पूरा अवसर मिला हो और उसने खुद अपना साक्ष्य बंद करा दिया हो तो बाद में अतिरिक्त गवाही की मांग के लिए ठोस कारण बताना होगा। न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने यह आदेश अलीगढ़ की रामघाट रोड स्थित दुकान से किरायेदार की बेदखली के मामले में दिया। किरायेदार ने 21 अप्रैल 2025 को अपनी गवाहों की सूची में हस्तलेखन विशेषज्ञ समीर शर्मा का नाम शामिल किया था। चार गवाहों के बयान दर्ज कराने के बाद 31 जुलाई 2025 को उसने कह दिया कि अब कोई अन्य साक्ष्य पेश नहीं करना है। इसके बाद अदालत ने उसका साक्ष्य बंद कर दिया और मुकदमे को अंतिम बहस के लिए रख दिया।

मकान मालिक की बहस पूरी होने और लिखित बहस दाखिल होने के बाद किरायेदार ने 21 फरवरी 2026 को विशेषज्ञ को गवाही के लिए बुलाने की अर्जी दी। उसकी अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। इसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि पक्षकार को पहले गवाह पेश नहीं करने का कारण और बाद में हुई देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा। केवल दस्तावेज की प्रासंगिकता या खर्च देने की पेशकश पर्याप्त नहीं है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेशों में कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई और अनुच्छेद 227 के तहत दाखिल याचिका खारिज कर दी। साथ ही ट्रायल कोर्ट को मुकदमे का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया।

राज्य विवि: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा सात दिसंबर को, 30 नवंबर को जारी होगा प्रवेश पत्र

प्रयागराज। प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) राज्य विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सात दिसंबर को 13 विषयों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) राज्य विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सात दिसंबर को 13 विषयों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें अंग्रेजी, कृषि विज्ञान, दर्शनशास्त्र, प्रबंधन अध्ययन, भूगोल, फार्मेसी, मनोविज्ञान व व्यवहार विज्ञान, लोक प्रशासन, विधि, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी और संस्कृत विषय शामिल हैं। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा दोपहर 12 बजे विश्वविद्यालय परिसर में होगी। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 30 नवंबर को शाम पांच बजे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे।

अल्लापुर हत्याकांड: अरविंद को मारी गईं नौ गोलियां, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

प्रयागराज। अल्लापुर में अरविंद भारतीया की हत्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वारदात की भयावहता सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, हमलावरों ने उन्हें नौ गोलियां मारी थीं। इनमें पांच चेहरे, तीन कंधे और एक पीठ पर लगी। आठ गोलियां शरीर के आर–पार हो गईं, जबकि एक गोली सीने में फंसी मिली, जिसे पोस्टमार्टम के दौरान निकाला गया।

अल्लापुर में अरविंद भारतीया की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अहम जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, अरविंद की मौत नौ गोलियां लगने से हुई थी। हमलावरों ने उनके चेहरे, कंधे और पीठ को निशाना बनाया था। पोस्टमार्टम के दौरान सीने में फंसी एक गोली भी बरामद हुई।

सूत्रों के अनुसार, अरविंद के चेहरे पर पांच, कंधे पर तीन और पीठ पर एक गोली लगी थी। इनमें से आठ गोलियां शरीर के आर–पार हो गई थीं, जबकि एक गोली सीने में फंसी मिली। पोस्टमार्टम के दौरान इस गोली को निकाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए इन तथ्यों से हत्या की वारदात की गंभीरता का पता चलता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।



बृहस्पतिवार की शाम को तड़तड़ाईं थीं गोलियां

अल्लापुर में बृहस्पतिवार शाम लगभग छह बजे एक सैलून में घुसकर हिस्ट्रीशीटर साजन मेहता हत्याकांड के मुख्य गवाह अरविंद भारतीया (30) पुत्र किसुन लाल की दो नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना अरविंद के घर से लगभग 200 मीटर दूर यूको बैंक तिराहे के पास एक सैलून में हुई। अरविंद अपनी मौसी के घर तिलक समारोह में जाने के लिए सेविंग कराने पहुंचा था। घटना के समय मौजूद लोगों ने बताया कि जब वह सेविंग के लिए कुर्सी पर बैठा, उसके कुछ ही देर बाद टोपी पहने तीन युवक गमछे से मुंह ढककर सैलून पहुंचे। नाई को बगल कर पहली गोली अरविंद के सिर के बीच में मारी।

पहली गोली चलते ही अफरातफरी का माहौल हो गया। इसी बीच अन्य दो आरोपियों ने भी गोली चला दी। घटनास्थल के पास मौजूद लोगों के मुताबिक, गोली मारने के बाद सैलून के बाहर खड़ी लगभग दस से 15 बाइक सवार भी वहां से भाग गए। लोगों ने अरविंद को एसआरएन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

चार साल पहले युवती से बना युवक, अब चेहरे पर दाढ़ी–मूंछ और आवाज में बदलाव

प्रयागराज। माता–पिता को खोने के बाद अकेलेपन और असुरक्षा से जूझ रही युवती ने अपनी पहचान बदलने का फैसला किया। चार साल पहले एसआरएन अस्पताल में उसकी लिंग परिवर्तन सर्जरी हुई थी। अब चेहरे पर दाढ़ी–मूंछ आ गई है और आवाज भी पुरुषों जैसी हो गई है। युवक का कहना है कि अब वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है और रात में भी अकेले आने–जाने से डर नहीं लगता।

फाफामऊ निवासी 20 वर्षीय युवती का 14 जून 2022 को एसआरएन अस्पताल में लिंग परिवर्तन किया गया था। सर्जरी की प्रक्रिया करीब एक साल तक कई चरणों में चली। बृहस्पतिवार को वह यूरोलॉजी विभाग में डॉ. दिलीप चौरसिया से मिलने पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए डॉक्टर को बताया कि वह वही मरीज है, जिसका लड़की से लड़का बनाया गया था।



इस सर्जरी में प्लास्टिक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. मोहित जैन और यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. दिलीप चौरसिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के चिकित्सकों ने भी सहयोग किया। प्रारंभिक सर्जरी डॉ. मोहित जैन की देखरेख में हुई, जबकि स्तन और गर्भाशय हटाने की प्रक्रिया स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग ने पूरी की। सर्जरी के बाद मरीज को हर तीन महीने पर हार्मोन का इंजेक्शन दिया जा रहा है। आगे की सर्जरी उसने किसी दूसरे स्थान पर कराने का निर्णय लिया है।

एसआरएन अस्पताल में यह सर्जरी करीब 50 हजार रुपये में की गई, जबकि निजी अस्पतालों में इस तरह की सर्जरी पर पांच लाख रुपये से अधिक खर्च आता है। डॉ. दिलीप चौरसिया के अनुसार, सर्जरी के बाद मरीज में शारीरिक, मानसिक और व्यवहार संबंधी बदलाव आए हैं। डॉ. मोहित जैन ने बताया कि यह कई चरणों में पूरी होने वाली जटिल सर्जरी थी। इसके करीब डेढ़ साल बाद शारीरिक बदलाव दिखने शुरू होते हैं। डॉक्टर के मुताबिक, फिलहाल मरीज में प्रजनन क्षमता नहीं है।

अब खुद को सुरक्षित महसूस करता है युवक

युवक ने बताया कि माता–पिता की मौत के बाद वह काफी अकेला पड़ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। ऐसे समय में रिश्तेदारों से ज्यादा दोस्तों ने मदद की। उसका कहना है कि कई लोग सांत्वना देने के बहाने उसका फायदा उठाने की कोशिश करते थे। इसी असुरक्षा के कारण उसने पुरुष के रूप में जीवन जीने का निर्णय लिया।

उसने बताया कि अब उसे रात में घर से निकलने में डर नहीं लगता और वह अपनी सुविधा से कहीं भी आ–जा सकता है। उसके पिता पुलिस विभाग में थे। ऐसे में अनुकंपा के आधार पर कुछ समय पहले उसे पुलिस विभाग में कार्यालय का कामकाज मिल गया है।

जॉब: प्रयागराज में पूर्व सैनिकों के लिए 1000 से अधिक नौकरियां, 40 कंपनियां देंगी रोजगार

प्रयागराज। सेना में देश की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले जवान अब कॉरपोरेट जगत में भी अपनी काबिलियत दिखाएंगे। प्रयागराज में आयोजित रोजगार मेले में 40 कंपनियों ने एक हजार से अधिक नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने की पहल की। सेना से सेवानिवृत्त होने वाले जवानों को दूसरा करियर देने की पहल के तहत शुक्रवार को प्रयागराज में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के पुनर्वास महानिदेशालय की ओर से आयोजित मेले में करीब 40 कॉरपोरेट कंपनियों ने हिस्सा लिया। इनके माध्यम से पूर्व सैनिकों के लिए एक हजार से अधिक रिक्तियों पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। मेले में करीब एक हजार पूर्व सैनिकों के शामिल होने की उम्मीद जताई गई।



इस मौके पर मेजर जनरल एसबीके सिंह, सेना मेडल, महानिदेशक पुनर्वास ने कहा कि सेना में करीब 35 से 40 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले जवानों को दूसरा करियर उपलब्ध कराना पुनर्वास महानिदेशालय की प्राथमिकता है। सैनिकों में अनुशासन, निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत जैसे गुण होते हैं। इनकी क्षमताओं का इस्तेमाल देश के विकास में भी किया जा सकता है। रोजगार मेला इसी दिशा में एक प्रयास है।

देश के हर हिस्से में आयोजित किए जाते हैं रोजगार मेले– उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों के लिए देश के अलग–अलग हिस्सों में हर साल करीब 18 से 20 रोजगार मेले आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष की श्रृंखला में प्रयागराज का मेला पांचवां है। पूर्व सैनिकों के लिए पारंपरिक नौकरियों के साथ आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर तलाशे जा रहे हैं।

मेजर जनरल सिंह ने बताया कि पूर्व सैनिक चालक, ड्रोन संचालक, तकनीकी एवं यांत्रिक कार्यों, मरम्मत, कंप्यूटर, साइबर सुरक्षा, लेखा, डेटा विश्लेषण और कृषि उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में काम करने में सक्षम हैं। इसके अलावा उन्हें स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कॉरपोरेट जगत और रोजगार मेले के आयोजन में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार जताया।

सड़क और श्मशान की जमीन पर दुकानें नहीं बना सकते, हाईकोर्ट ने 18 दुकानदारों की याचिकाएं खारिज की

प्रयागराज। सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर निजी कारोबार खड़ा करने की अनुमति नगर निकाय भी नहीं दे सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि सड़क और श्मशान के लिए दर्ज सरकारी जमीन पर दुकानें बनाना या उनका आवंटन करना कानूनन वैध नहीं है। इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने बांदा के 18 दुकानदारों को राहत देने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नगर निकाय सड़क और श्मशान जैसे सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर न दुकानें बना सकती है न ही आवंटित कर सकती है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने बांदा के 18 दुकानदारों की याचिकाएं खारिज कर दीं। मामला नगर पंचायत बबेरू का है। नगर पंचायत ने दो मंजिला व्यावसायिक परिसर बनाकर वर्ष 2010 और 2016 में दुकानों का आवंटन किया था। दुकानदारों ने प्रीमियम, किराया और सुरक्षा राशि जमा करने के साथ दुकानों में काफी पैसा खर्च किया था।

उन्होंने नगर पंचायत के तीन अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए दुकानों को गिराने पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि निर्माण नगर पंचायत ने कराया और दुकानें भी उसी ने आवंटित कीं। ऐसे में उन्हें अतिक्रमणकारी नहीं माना जा सकता। दुकानदारों ने पट्टा समाप्त करने से पहले संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा–106 के तहत छह माह का नोटिस नहीं देने पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने क्षेत्रीय लेखपाल की 15 जनवरी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि व्यावसायिक परिसर गाटा संख्या 680 और 769 पर बना है। इनमें गाटा संख्या 680 बबेरू–राजापुर सड़क और गाटा संख्या 769 श्मशान के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इन प्रविष्टियों को गलत साबित करने के लिए याचियों ने न तो कोई राजस्व अभिलेख पेश किया और न ही सीमांकन की मांग की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 293(1) नगर निकाय को ऐसी सरकारी जमीन पट्टे पर देने का अधिकार नहीं देती, जिस पर उसका वैध नियंत्रण नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा–106 का नोटिस संबंधी प्रावधान भी सरकारी जमीन पर पट्टा देने के अधिकार की कमी को दूर नहीं कर सकता। सार्वजनिक सड़क और श्मशान की जमीन पर अनधिकृत निर्माण को खर्च की गई रकम या न्यायसंगत रोक के सिद्धांत से वैध नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एमआई बिल्डर्स और जगपाल सिंह मामलों का हवाला देते हुए कहा कि सार्वजनिक उपयोग की जमीन को निजी कब्जे के लिए नियमित नहीं किया जा सकता।

बिना सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी पुलिसकर्मियों पर नहीं चलेगा मुकदमा, हाईकोर्ट ने रद की कार्यवाही

प्रयागराज। सरकारी ड्यूटी के दौरान किए गए कथित कृत्य के लिए पुलिसकर्मियों को सीधे अदालत में नहीं घसीटा जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी जरूरी है। इसी आधार पर कोर्ट ने बांदा के तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी ड्यूटी के दौरान कथित रूप से किए गए किसी गलत काम के लिए संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी जरूरी है। इस टिप्पणी संग कोर्ट ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन ने बांदा के तत्कालीन थाना प्रभारी केएन मिश्रा और दो अन्य पुलिसकर्मियों की याचिका पर दिया है।

बांदा जिले के गिरवां थाना क्षेत्र में परिवादी योगेंद्र मिश्रा का जमीन पर बाउंड्रीवॉल बनवाने को लेकर पड़ोसियों से विवाद चल रहा था। आरोप था कि 11 मई 2013 की रात आरोपी पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे। उन्होंने बाउंड्रीवॉल का निर्माण रुकवा दिया धमकी दी और गाली–गलौज की। परिवादी की ओर से दर्ज कराए गए परिवाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चार मार्च 2014 को समन जारी किया। इस फैसले को याची पुलिसकर्मियों ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए पूरी कार्यवाही रद करने की गुहार लगाई। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि संबंधित भूमि पर विवाद के कारण शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी। पुलिसकर्मी कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने सरकारी दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। कथित घटना का संबंध उनकी आधिकारिक ड्यूटी से था इस कारण धारा 197 सीआरपीसी के तहत सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सरकारी ड्यूटी से सीधे जुड़े कथित कृत्य के लिए अभियोजन से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी आवश्यक थी। ऐसी मंजूरी के बिना जारी समन आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए समन आदेश समेत पूरे आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही रद कर दी।

प्रयागराज–हुब्बल्लि स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े, जारी किया गया टाइम टेबल

प्रयागराज। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने प्रयागराज–हुब्बल्लि स्पेशल ट्रेन (04113/04114) के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से गाड़ी–04113 प्रयागराज जंक्शन से अब 19 और 26 दिसंबर को भी चलेगी। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने प्रयागराज–हुब्बल्लि स्पेशल ट्रेन (04113/04114) के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से गाड़ी–04113 प्रयागराज जंक्शन से अब 19 और 26 दिसंबर को भी चलेगी। हर शनिवार सुबह 5रू05 बजे प्रयागराज जंक्शन से रवाना होकर ट्रेन फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, भिंड, ग्वालियर और भोपाल के रास्ते 2,968 किमी का सफर तय करते हुए सोमवार दोपहर 3रू10 बजे हुब्बल्लि पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी–04114 हुब्बल्लि से 22 और 29 दिसंबर को चलाई जाएगी। मंगलवार सुबह 9रू00 बजे हुब्बल्लि से चलकर यह ट्रेन बृहस्पतिवार रात 10रू40 बजे जंक्शन आएगी। 23 कोच वाली इस विशेष ट्रेन में सामान्य श्रेणी के आठ, स्लीपर के 11, एसी तृतीय श्रेणी के दो और दो एसएलआरडी कोच लगाए गए हैं।

शाहदरा स्टेशन पर नहीं रुकेगी महानंदा एक्सप्रेस

उत्तर रेलवे ने दिल्ली–गाजियाबाद रेलखंड पर कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला है। यह बदलाव दिल्ली शाहदरा यार्ड में ट्रैफिक ब्लॉक कार्य की वजह से किया गया है। जिन ट्रेनों का रूट बदला गया है उसमें प्रयागराज आने वाली महानंदा एक्सप्रेस भी शामिल है। गाड़ी–15483 अलीपुरद्वार जंक्शन–दिल्ली महानंदा दो जनवरी को परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। इसका नया मार्ग साहिबाबाद, दिल्ली सफदरजंग, नई दिल्ली और दिल्ली जंक्शन होगा। इस मार्ग परिवर्तन के कारण दिल्ली शाहदरा स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा।

संक्षिप्त

खादी महोत्सव का उद्घाटन खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने किया

लखनऊ, संवाददाता। राजधानी में खादी महोत्सव शुरू हो गया है। गोमती नगर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में 27 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलने वाले महोत्सव में खादी और ग्रामोद्योग के 150 स्टॉल लगाए गए हैं। यहां कपड़ों से लेकर ग्रामीण उद्योगों के उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। महोत्सव का उद्घाटन खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने किया। इस मौके पर उन्होंने चरखा चलाया। महोत्सव की थीम 'धागों में संस्कृति, खादी से प्रगति' रखी गई है। इसमें प्रदेश के अलग–अलग जिलों से आए उद्यमी और शिल्पकार अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि खादी केवल कपड़ा नहीं, बल्कि स्वाभिमान, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पिछले 5 साल में 2,544.35 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया। इससे 24,799 ग्रामोद्योग इकाइयां स्थापित हुईं और 2.79 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला। प्रदेश के 18 मंडलों में अब तक 115 प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं। इनमें 27,508 स्टॉल लगाए गए, जिनके माध्यम से 161 करोड़ 54 लाख रुपये से अधिक के उत्पादों की बिक्री हुई। मंत्री ने बताया कि गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर से खादी वस्त्रों और गारमेंट्स पर 30 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है। खादी में अब पारंपरिक कपड़ों के साथ आधुनिक डिजाइन और फैशन के विकल्प भी उपलब्ध हैं। उन्होंने युवाओं से खादी अपनाने और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने की अपील की। मंत्री ने लखनऊ के लोगों से महोत्सव में पहुंचकर खादी और ग्रामोद्योग के उत्पाद खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलने से बुनकरों, शिल्पकारों और ग्रामीण उद्यमियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

राजधानी में अगले 48 घंटे में गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड

लखनऊ, संवाददाता। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार सुबह हल्की धुंध रही, बाद में मौसम साफ हो गया। दिन में धूप निकलने से ठंड से राहत रहेगी। अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक है। सुबह और शाम ठंड का असर रहेगा, जबकि दिन में मौसम अपेक्षाकृत आरामदायक रहेगा। हवा में अधिकतम नमी 89: और न्यूनतम 45: दर्ज की गई। लखनऊ में सुबह के समय छह निगरानी केंद्रों का औसत एक्यूआई 148 दर्ज किया गया, जबकि 26 नवंबर को शाम 5 बजे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक शहर का एक्यूआई 143 के साथ यलो जोन में रहा। हालांकि, सुबह के समय शहर के अलग–अलग इलाकों में स्थिति में फर्क दिखा, जहां कुकरैल पिकनिक स्पॉट–1 में एक्यूआई 98 और बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 130 रहा, जबकि गोमती नगर में 109, तालकटोरा में 161 के साथ में लालबाग में 191 एक्यूआई दर्ज किया गया। केंद्रीय विद्यालय अलीगंज में 201 के साथ ऑरेंज जोन में दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार ने बताया लखनऊ में सूखी और ठंडी उत्तर–पश्चिमी हवाएं चलने से ठंड और बढ़ने की उम्मीद है। अब अगले 48 घंटों में तापमान थोड़ा और गिर सकता। पारा सामान्य या उससे नीचे जा सकता है। जिससे ठंड बढ़ सकती है।

स्वास्थ्य मिशन कर्मचारीयों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया

लखनऊ, संवाददाता। राजधानी में विधान भवन के बाहर स्वास्थ्य मिशन और ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे कर्मचारियों ने विधान भवन का घेराव कर नियमित काम और निश्चित मानदेय की मांग उठाई। कर्मचारियों ने शासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जल्द मांगें पूरी करने की अपील की। ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर एक अक्टूबर 2023 को नैमिषारण्य सम्मेलन में किए गए न्यूनतम वेतन के वादे को पूरा करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि स्वच्छताग्राहियों ने गांवों में शौचालय निर्माण और खुले में शौच मुक्त अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। कोरोना काल से लेकर लोकसभा और विधानसभा चुनावों तक उनसे ड्यूटी कराई गई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नियमित काम और निश्चित मानदेय नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में उन्हें नियमित काम दिया जाए और निश्चित मानदेय तय किया जाए। उनका कहना है कि काम और वेतन की व्यवस्था नहीं होने से परिवार के सामने रोजी–रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने शासन से जल्द न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग की है। कर्मचारियों ने कहा कि एक महीने से धरने पर बैठे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। हम सभी ने 2024 में भी धरना दिया था। उस समय तत्कालीन डीपीआओ हिंमाशु शेखर ने कहा था कि सरकार ने आपकी मांग पूरी कर ली गई है। इसके बाद हम सभी ने धरना खत्म कर दिया था। लेकिन कोई भी हमारी मांग आज तक नहीं मानी गई। जब तक सरकार हमारे बारे में नहीं सोचेगी। तब तक हम सभी लोग यहीं धरने पर बैठे रहेंगे।

लगातार दूसरी बार उर्दू अकादमी के चेयरमैन बने कैफुल वरा अंसारी

लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार ने उर्दू अकादमी की नई कार्यकारिणी परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। गोरखपुर के चौधरी कैफुल वरा अंसारी को लगातार दूसरी बार अकादमी का चेयरमैन नामित किया गया है। उन्होंने दोबारा जिम्मेदारी मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। कहा कि अकादमी के अधूरे काम पूरे कराना और उर्दू भाषा–साहित्य का प्रचार–प्रसार उनकी प्राथमिकता होगी। नई कार्यकारिणी में वित्त, भाषा और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष, उर्दू शिक्षा निदेशालय के निदेशक और उर्दू अकादमी के सचिव पदेन सदस्य होंगे। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभागाध्यक्षों को भी पदेन सदस्य बनाया गया है। गैर सरकारी सदस्यों में लखनऊ के मो. नईम, खुर्शीद आलम और शादाब आलम समेत प्रदेश के अलग–अलग जिलों से 11 अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें बिजनौर के डॉ. इमरान सलमानी, पीलीभीत की फरहा नाज, फतेहपुर के मोईन अहमद खान, बुलंदशहर के नदीम अख्तर, संत कबीर नगर के जिरगाम खान, रामपुर के वसीम खान, अमरोहा के महमूद हसन उर्फ बब्बू मंसूरी, अंबेडकरनगर की चांदनी बानो और मऊ के जुलकर नैन अंसारी शामिल हैं।

सी.एम.पी. महाविद्यालय में संविधान दिवस समारोह का भव्य आयोजन

प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय चौधरी महादेव प्रसाद (सी.एम.पी.) डिग्री कॉलेज के विधि विभाग द्वारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में महाविद्यालय के नवीन सभागार में एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय संविधान के मूल आदर्शों, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय तथा नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना था।



समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यसभा सदस्य एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधाकांत ओझा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता चौधरी कौशलेन्द्र नाथ सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम का आयोजन के. पी. ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं मुख्य संरक्षक चौधरी राघवेन्द्र नाथ सिंह तथा महाविद्यालय के प्राचार्य एवं कार्यक्रम के संरक्षक प्रो. अजय प्रकाश खरे के संरक्षण में किया गया। कार्यक्रम के संयोजक विधि विभाग के प्रो. शिव शंकर सिंह रहे। कार्यक्रम का कुशल एवं प्रभावशाली संचालन डॉ. अमित मिश्रा द्वारा किया गया।

समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के साथ हुआ। इसके पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अजय प्रकाश खरे ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया तथा अतिथियों का अभिनंदन किया।

इस अवसर पर डॉ. रमेश कुमार सिंह के नेतृत्व में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। उपस्थित अतिथियों, शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों ने इसमें सहभागिता करते हुए संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता के मूल आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि चौधरी कौशलेन्द्र नाथ सिंह ने अपने संबोधन के माध्यम से विधि विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया।

मुख्य अतिथि श्री राधाकांत ओझा ने समारोह को संबोधित किया। राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में विधि, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था से जुड़े उनके अनुभव ने इस अवसर को विशेष महत्त्व प्रदान किया। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए कानून के दायरे में रहकर संविधान का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों के पालन के लिए जागरूक किया जिससे देश के विकास में वह सहभागी बन सकें। उन्होंने संविधान में अंतर्निहित संविधान की मूल भावना को समझाते हुए कहा कि भारतीय संविधान सर्वे भवंतु सुखिनरू की परिकल्पना पर आधारित है। उन्होंने उद्देश्य का का वर्णन करते हुए बताया की उद्देशिका में हमारे मूल अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य सब अंतर्निहित हैं।

समारोह में विधि विभाग के शिक्षकगण, डॉ अजय प्रताप सिंह, डॉक्टर अजय कुमार, डॉ पूर्णेन्दु मिश्रा, डॉ पद्मा अपराजिता परिजा,डॉक्टर डॉ नंदिनी रायजादा, डॉ रितु रघुवंशी, डॉ सोनल खरे, डॉ रमेश कुमार भारती, डॉ अंजलीका,डॉ रेनू सिंह, डॉ गौरव पटेल, डॉ सत्यवान नायक, डॉ अनुश्री व महाविद्यालय के अन्य वरिष्ठ प्रोफेसर, शोधार्थी, विद्यार्थी एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग के प्रोफेसर शैलेंद्र मिश्रा व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर स्थाई अधिवक्ता श्री संतोष शुक्ला व अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया तथा राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ ।

एक्शन मोड में नगर निगमः

अतिक्रमण के खिलाफ दूसरे दिन भी चला महाअभियान, 150 मीटर तक हटाया गया अवैध कब्जा, 125 लोगों को नोटिस जारी

प्रयागराज। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम प्रयागराज पूरी तरह से एक्शन मोड में है। अभियान के दूसरे दिन आज नगर निगम की टीम ने जोन–4 में सड़क और फुटपाथ पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।

इस दौरान कुंदन गेस्ट हाउस से लेकर 80 फीटा रोड तक लगभग 150 मीटर के दायरे में सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को जमींदोज कर हटाया गया। इस कार्रवाई की जद में 12 लोगों के अवैध निर्माण आए, जिन्हें टीम द्वारा ध्वस्त कर मार्ग को सुगम बनाया गया।



विभिन्न क्षेत्रों में 125 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी

ध्वस्तीकरण के साथ–साथ नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में सड़क व फुटपाथ घेरने वाले कुल 125 लोगों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए गए हैं, जिनका क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार हैरू

करेली एवं झलवारू 64 लोग

ममफोर्डगंज एवं सलोरीरू 33 लोग

नैनीरू 15 लोग

ट्रांसपोर्ट नगररू 13 लोग

नगर निगम की अपील एवं चेतावनी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान कल भी जारी रहेगा और शहर के हर हिस्से में इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने समस्त अतिक्रमणकारियों से पुनः अपील की है कि जिन लोगों ने सड़क, फुटपाथ अथवा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया है, वे स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें। निर्धारित समय में कब्जा न हटाने पर नगर निगम द्वारा कठोर कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण का खर्च व भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा, साथ ही संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

प्रयागराज नगर निगम की बड़ी उपलब्धिः एयरपोर्ट अथॉरिटी से तीन वर्षों के बकाया गृहकर की ₹2.17 करोड़ की वसूली

तीन साल का गृहकर बकाया वसूला, नगर निगम ने रचा राजस्व सफलता का नया अध्याय

प्रयागराज। प्रयागराज नगर निगम द्वारा राजस्व वसूली को प्रभावी एवं गतिशील बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे निरंतर प्रयासों के क्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। नगर निगम द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से विगत तीन वर्षों से लंबित बकाया गृहकर के सापेक्ष ''2,17,20,823/– (रुपये दो करोड़ सत्रह लाख बीस हजार आठ सौ तेईस मात्र)'' की धनराशि सफलतापूर्वक वसूल की गई है। यह उपलब्धि नगर निगम की सुदृढ़ राजस्व प्रबंधन व्यवस्था, प्रभावी कर वसूली अभियान तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सतत प्रयासों का परिणाम है। तीन वर्षों से लंबित इतनी बड़ी धनराशि की वसूली से नगर निगम के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नगर निगम प्रशासन द्वारा बड़े बकायेदारों से राजस्व वसूली को प्राथमिकता देते हुए निरंतर अनुश्रवण, प्रभावी कार्यवाही एवं समन्वय के माध्यम से लंबित कर की वसूली सुनिश्चित की जा रही है। इस क्रम में एयरपोर्ट अथॉरिटी से प्राप्त यह धनराशि नगर निगम की राजस्व वसूली अभियान की एक महत्वपूर्ण सफलता है। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर के विकास कार्यों, नागरिक सुविधाओं के विस्तार एवं आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राजस्व की नियमित एवं प्रभावी वसूली अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सभी बड़े बकायेदारों से बकाया कर जमा कराने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयागराज नगर निगम की अपील है कि सभी भवनस्वामी एवं संस्थान अपना गृहकर समय से जमा करें तथा नगर के विकास में सहभागी बनें।

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बंपर निवेश

5,246 करोड़ की परियोजनाओं से महिलाओं व युवाओं को रोजगार

लखनऊ, संवाददाता। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मार्गदर्शन में खाद्य प्रसंस्करण विभाग प्रदेश की महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के नए अवसर प्रदान करने की दिशा में निरंतर ऐतिहासिक कदम उठा रहा है।अपर मुख्य सचिव खाद्य प्रसंस्करण बीएल मीणा ने विभाग की अद्यतन प्रगति का विवरण देते हुए बताया कि 27 नवंबर तक खाद्य संस्करण 2023 नीति के अंतर्गत कुल 2,084 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 630 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और 628 उद्यमियों को श्लेटर ऑफ कम्फर्टश निर्गत किए जा चुके हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 5,246.20 करोड़ रुपये है, जिससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हो रहा है।आगामी एसएलईसी बैठक में निर्णयार्थ 67 नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की झलक देखने को मिल रही है, क्योंकि कुल 67 नए प्रस्तावों में से 31 प्रस्ताव श्प्रेरणा महिला लघु उद्योगश एवं महिला उद्यमियों से संबंधित हैं। ये महिला समूह संतकबीरनगर, हरदोई, बस्ती, सोनभद्र, देवरिया, औरैया, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, झांसी, मिर्जापुर, बलरामपुर, सुल्तानपुर और गोरखपुर जैसे जनपदों में रेडी टू कुक खाद्य इकाइयों पर सोलर पावर प्लांट स्थापित कर स्वच्छ ऊर्जा के साथ–साथ स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही हैं। अब तक प्रदेश भर में सोलर पावर प्लांट और टेक होम राशन से जुड़ी सर्वाधिक 139 परियोजनाओं को एलओसी जारी की जा चुकी है।

सजा जब मन का उपवन

(छप्पय)

शब्दों का है खेल कहानी कविता लिखना।
रचकर नूतन भाव जगत में हरदम दिखाना।
अक्षर–अक्षर जोड़ सजा जब मन का उपवन।
महक उठा संसार दफ़न कर सारे अनबन।
शब्द–साधना ही सदा करती जग कल्याण है।
कविता के हर छन्द में ज्ञान–सरित अति गूढ़ है।।

नदिया पर्वत फूल प्रकृति की प्यारी कविता।
रचती ऐसा लोक जहाँ रहती हैं सविता।
मोती का संसार पिरोकर वह माला में।
भर देती है ज्योति तमस की हर शाला में।
प्रकृति जनित हर शब्द का नाता बहुत अज़ीज़ है।
कण–कण में सौन्दर्य का अनुपम नव्य ज़मीन है।।

डॉ. प्रदीप चित्रांशी
लूकरगंज, प्रयागराज

दो साल बाद भी नहीं भूला परिवार, देव की याद में नम हुई आंखें

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्र भेजकर अर्पित किए श्रद्धासुमन, उपज जिलाध्यक्ष अतुल जिंदल ने दी सांत्वना

गोवर्धन। वक्त गुजरता रहा, लेकिन बेटे को खोने का दर्द आज भी परिवार के दिल में बरकरार है। दो वर्ष पूर्व असमय दुनिया छोड़ गए युवा देव शर्मा की द्वितीय पुण्यतिथि पर माहौल भावुक हो गया। 27 नवंबर 2024 को स्कूल से घर लौटते समय देव शर्मा का निधन हो गया था। शुक्रवार को उनकी पुण्यतिथि पर पत्रकारों और गणमान्य लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर याद किया। मीडिया कर्मी उत्तम शर्मा के युवा पुत्र देव शर्मा की पुण्यतिथि पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने अपने सूचना अधिकारी रतन सिंह के माध्यम से उत्तम शर्मा को पत्र भेजकर दिवंगत देव शर्मा के प्रति श्रद्धा–सुमन अर्पित किए और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नालिस्ट (उपज), मथुरा के जिलाध्यक्ष अतुल कुमार जिंदल ने भी देव शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शोकाकुल परिवार को सांत्वना देते हुए इस कठिन समय में धैर्य और हिम्मत बनाए रखने का संबल दिया। पत्रकारों ने भी दिवंगत देव शर्मा को याद कर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उत्तम शर्मा के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।



मतदाता जागरूकता रथ के साथ 200 विद्यार्थियों ने निकाली रैली

ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए किया प्रेरित

सोनई। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज, सोनई के मतदाता साक्षरता क्लब (ईएलसी) की ओर से 28 और 29 नवंबर को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के तहत करीब 200 विद्यार्थियों ने मतदाता जागरूकता रथ के साथ रैली निकालकर ग्रामीणों को मतदान के प्रति जागरूक किया।



रैली का शुभारंभ प्रधानाचार्य डॉ. अखिलेश कुमार यादव, आयुक्त स्काउट श्री हरिओम और श्रीमती शिखा मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। विद्यार्थियों ने पोस्टर और नारों के माध्यम से मताधिकार के महत्व, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागिता का संदेश दिया।

रैली सोनई थोक ज्ञान, थोक कमल, थोक वृंदावन और सुम्मेरा सहित आसपास के क्षेत्रों से होकर गुजरी। विद्यार्थियों ने विशेष रूप से एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया।

प्रधानाचार्य डॉ. अखिलेश कुमार यादव ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जागरूक मतदाता आवश्यक हैं। युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करना अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी है। विद्यालय का मतदाता साक्षरता क्लब विद्यार्थियों के माध्यम से समाज तक मतदाता जागरूकता का संदेश पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। रैली में विद्यार्थियों और विद्यालय स्टाफ ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए जागरूक मतदाता, मजबूत लोकतंत्र का संदेश दिया।

पूर्वोत्तर रेलवे
ई–टेन्डरिंग निविदा सूचना
भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये मंडल रेल प्रबन्धक (इंजी०)/वाराणसी निम्नलिखित कार्य हेतु आनलाईन (ई–टेन्डरिंग) के माध्यम से "खुली" निविदा आमंत्रित करते है। कार्य का नाम:– छपरा – औड़िहार अनुभाग – टीटीआर (एफएस+टीडब्लूएस+डब्लूसीएमएस) – 122 सेट (1 इन 12) ई–निविदा सूचना सं०:– एनईआर–बीएसबी–2026–152, अनुमानित लागत (₹):– 5,66,62,034/–, अमानत राशि (बिड सिक्यूरिटी) (₹):– 11,33,300/–, निविदा बन्द होने की तिथि:– 22.12.2026, स्वीकृत पत्र जारी होने के समय से कार्य समापन/अवधि की तिथि:– 18 माह, • निविदा सूचना संख्या एनईआर–बीएसबी–2026–152 दिनांक 22.12.2026 को 11:30 बजे तक आनलाईन जमा कर सकेंगे। • पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेल के वेब साइट www.ireps.gov.in पर देखें। • यदि निविदा सूचना में हिन्दी एवं अंग्रेजी में अंतर होता है तो निविदा सूचना में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
मण्डल रेल प्रबन्धक/(इन्जी०)
मुजामि/डब्लू–423 वाराणसी
ट्रेनों में बीड़ी/सिगरेट न पियें

सम्पादकीय.....

सूर्य जैसा वैभव

यह कल्पना से परे है कि कोई पंद्रह वर्षीय किशोर क्रिकेट के खेल में महज 52 गेंदों में दोहरा शतक बना दे। इतना ही नहीं, 28 बॉल में शतक भी जड़ दे। साथ ही सबसे तेज 150 रन महज 40 गेंदों में बना डाले। एक पारी में 28 छक्कों का अविश्वसनीय कारनामा। यानी 204 रनों की पारी में 168 रन सिर्फ छक्कों से बटोर लिए, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड हैं। ये कारनामा मंगलवार को वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट ए क्रिकेट के दोहा में हुए एक मैच में कर दिखाया। कहा जा रहा है कि इस टीनएजर ने क्रिकेट को वीडियो गेम बना डाला। आज दुनिया के क्रिकेट जगत में सूर्यवंशी के खेल–वैभव की चर्चा हो रही है। क्रिकेट के दिग्गज उनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। साथ ही सवाल भी पूछ रहे हैं कि उन्हें टी–20 व वन डे की भारतीय टीम में बतौर ओपनर कब जगह मिल पायेगी? उल्लेखनीय है कि वे दस इंटरनेशनल टी–20 मैचों में 185 के स्ट्राइक रेट से 295 रन बना चुके हैं। इतना ही नहीं ,आईपीएल की अब तक खेली 23 पारियों में उन्होंने 228 के स्ट्राइक रेट से 1028 रन बनाये हैं। वहीं आईपीएल सीजन में भी उन्होंने क्रिस गेल जैसे दिग्गज क्रिकेटर द्वारा एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। इस किशोरवय सनसनी ने आईपीएल सीजन 2026 में 72 छक्के जड़े थे। यही वजह है कि अक्सर उनके आक्रामक खेल और छक्के मारने के कौशल की चर्चा होती है। दुनिया के अन्य देशों में उनके इस चमत्कारी हुनर की चर्चा खूब हो रही है। यहां तक कि मंगलवार को पाकिस्तान द्वारा दोहा में अपना ग्रुप का मैच जीतने के बावजूद वहां सिर्फ वैभव के आतिशी खेल की चर्चा होती रही। निस्संदेह, छोटी उम्र में वैभव की कामयाबी अप्रत्याशित है। वे मौलिक खेल प्रतिभा के धनी हैं। अभी उनका लंबा क्रिकेट जीवन होना है। यही वजह है कि वैभव की प्रतिभा और फुल फॉर्म में होने की वजह से भारतीय टीम में उनकी जगह सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है। जाहिर है इस समय दुनिया के दिग्गज गेंदबाज उनके खेल को पढ़ रहे होंगे। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय पिचों व गेंदबाजों को उन्हें समझना होगा। जिसके लिये वैभव को अपने खेल कौशल को और समृद्ध करने की जरूरत होगी। निस्संदेह, अविश्वसनीय कामयाबी वाले वैभव के पास भविष्य में तमाम मौके आने वाले हैं। बीसीसीआई को उनको लेकर संतुलित नीति अपनाने की जरूरत होगी। कुछ लोगों का मानना है कि मौलिक व आक्रामक खेल वाले खिलाड़ी विरले ही पैदा होते हैं, लेकिन समय पर बड़े अवसर न मिलने का नकारात्मक प्रभाव उनके खेल में पड़ सकता है। क्रिकेट समीक्षक सोलह साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ 1989 में मौका देने और उसके बाद उनकी अप्रत्याशित कामयाबी का जिक्र भी करते हैं। निस्संदेह, ऐसे में विरले ही सामने आने वाली विशिष्ट प्रतिभाओं को मानसिक संबल देने की जरूरत होगी। वैभव जैसे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते हुए बेतहरीन खेल रहे हैं तो उसी अनुपात में उन्हें अच्छे अवसर भी मिलने चाहिए। आईपीएल सीजन 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल करना उनकी प्रतिभा को ही दर्शाता है। साथ ही जरूरी है कि वैभव अपने आक्रामक खेल को बनाये रखें। उसमें निरंतरता रहे और वे क्रिकेट की आधुनिक तकनीकों से रूबरू होते रहें। निश्चित रूप से अधिक इंटरनेशनल मैच खेलना, उनके खेल में निखार लाएगा। जाहिर है उनकी हालिया आतिशी पारी के बाद दुनिया के तमाम गेंदबाज उन पर हावी होने के रास्ते तलाश रहे होंगे। वे उनकी असाधारण प्रतिभा को काबू करने के नुस्खे तलाश रहे होंगे। उनकी हिटिंग पावर को रोकने की व्यूह रचना की जा रही होगी। सुखद है कि दोहा के मंगलवार के मैच में जितने छक्के वैभव ने लगाये, कोई पूरी टीम भी उतने छक्के नहीं लगा सकती। कहा जा रहा है कि यह रिकॉर्ड तो सिर्फ वैभव ही तोड़ सकते हैं क्योंकि वे एक नैसर्गिक प्रतिभा के धनी है। निस्संदेह, जिस प्रतिष्ठा व उपलब्धि को क्रिकेटर सालों खेलने के बाद पाते हैं, उसे उन्होंने किशोरावस्था में ही पा लिया है।

चुनौती तक: अखिलेश का घोषणापत्र, पुराने वादों का हिसाब और योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड

2027 के चुनाव से पहले सपा ने रोजगार, सामाजिक न्याय, आरक्षण और किसान हितों को बनाया चुनावी एजेंडा, सवाल यह है कि नए वादे कितने व्यावहारिक हैं और पुराने वादों का कितना हिसाब दिया गया है?'

'लोकतंत्र में घोषणापत्र राजनीतिक दल का वचन होता है और जनता का सवाल उसका अधिकार। उत्तर प्रदेश की जनता को अब नारों से अधिक स्पष्ट नीति, रोजगार की गारंटी, किसान की समृद्धि, महिला की सुरक्षा, सामाजिक न्याय और जवाबदेह शासन चाहिए। 2027 की चुनावी बहस में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही होना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, उससे भी अधिक यह कि उसके वादों को पूरा करने की योजना कितनी स्पष्ट और व्यावहारिक है।

परवेज आलम
पत्रकार/सामाजिक विचारक एवं स्तंभकार

उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ राजनीतिक दलों ने अपने एजेंडे और प्राथमिकताएं स्पष्ट करनी शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को पार्टी का नया घोषणापत्र जारी किया। इसे श्जन–मन का मैनिफेस्टोश और श्सत्ताइस का संकल्प, पीडीए का प्रणपत्रश नाम दिया गया है। इस घोषणापत्र का केंद्रीय विचार पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी बढ़ाना है। लेकिन इस बार सपा का घोषणापत्र केवल सामाजिक समीकरणों तक सीमित नहीं है। इसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला सुरक्षा, बिजली और पुरानी पेंशन जैसे विषयों को भी प्रमुखता दी गई है।इस घोषणापत्र को समझने के लिए तीन सवालों पर विचार करना जरूरी है। पहला, सपा ने 2022 के चुनाव में क्या वादे किए थे और अब किन नए वादों के साथ सामने आई है? दूसरा, मौजूदा योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में रोजगार, कानून–व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं के मोर्चे पर क्या काम किए हैं? और तीसरा, क्या दोनों राजनीतिक पक्ष अपने दावों और वादों को स्पष्ट वित्तीय तथा प्रशासनिक योजना के साथ जनता के सामने रख रहे हैं?

'2022 के वचनपत्र से 2027 के प्रणपत्र तकरू बदला एजेंडा, कायम रोजगार और किसान का सवाल'

समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में श्समाजवादी वचन पत्रश जारी किया था। उस समय पार्टी ने घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), किसानों को 2025 तक कर्जमुक्त करने और पांच वर्षों में 22 लाख रोजगार देने का वादा किया था। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण, छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और इंटर पास विद्यार्थियों को लैपटॉप देने जैसे प्रस्ताव भी शामिल थे। 2026 के नए घोषणापत्र में रोजगार का लक्ष्य बढ़ाकर 25 लाख सरकारी नौकरियां करने की बात कही गई है। बेरोजगार स्नातकों को नौकरी मिलने तक पांच हजार रुपये मासिक भत्ता देने, जाति आधारित जनगणना कराने, सरकारी ठेकों में पीडीए वर्गों को हिस्सेदारी देने और पांच रुपये में भोजन उपलब्ध कराने वाली समाजवादी कैंटीन शुरू करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों के लिए सालाना 40 हजार रुपये की सहायता, गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपये तक स्वास्थ्य सुरक्षा और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की बात भी कही गई है।

यहां एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देता है। 2022 में सपा का जोर रोजगार सृजन, बिजली और किसान कल्याण पर था, जबकि 2027 के घोषणापत्र में रोजगार के साथ सामाजिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक हिस्सेदारी को अधिक स्पष्ट राजनीतिक स्वरूप दिया गया है। पुराने घोषणापत्र में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव था, जबकि नए दस्तावेज में महिलाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंद परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणाएं प्रमुखता से रखी गई हैं।

'पुराने वादों का हिसाब देना भी जरूरी'

लोकतंत्र में घोषणापत्र केवल भविष्य का सपना नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए जवाबदेही का दस्तावेज भी होना चाहिए। इसलिए सपा के नए घोषणापत्र पर चर्चा करते समय 2022 के वादों का हिसाब लेना भी आवश्यक है।मसलन, 2022 में 22 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था। अब 25 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। सवाल है कि पिछले लक्ष्य के मुकाबले कितने रोजगार सृजित हुए, कितनी नियुक्तियां हुईं और कितने पद रिक्त रह गए? इसी प्रकार 2025 तक किसानों को कर्जमुक्त बनाने का वादा किया गया था। पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि उसके प्रस्तावित किसान ऋण मुक्ति कार्यक्रम से कितने किसानों को लाभ मिल सकता है और इसके लिए कितने बजट की आवश्यकता होगी।300 यूनिट मुफ्त बिजली और सभी फसलों पर एमएसपी के वादे भी 2022 में किए गए थे। अब नए घोषणापत्र में इन्हें फिर से प्रमुखता मिली है। इसका अर्थ है कि ये मुद्दे अभी भी राजनीतिक और आर्थिक बहस के केंद्र में हैं। मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि पिछली बार सत्ता में न आने के कारण कौन–से वादे लागू नहीं हो सके और यदि भविष्य में सरकार बनी तो उन्हें लागू करने की समयसीमा तथा वित्तीय व्यवस्था क्या होगी। यह भी ध्यान रखना होगा कि 2022 के वादों को लागू करने का अवसर सपा को नहीं मिला, क्योंकि वह सरकार नहीं बना सकी। इसलिए उन्हें अधूरे सरकारी काम बताना उचित नहीं होगा। लेकिन अपने पुराने चुनावी वादों की प्रगति, अनुभव और व्यावहारिकता पर जनता को जवाब देना पार्टी की राजनीतिक जिम्मेदारी जरूर है।

'योगी सरकार के नौ वर्षों का रिपोर्ट कार्डरू रोजगार, विकास और कानून–व्यवस्था'



दूसरी ओर प्रदेश में 2017 से सत्ता संभाल रही भाजपा सरकार के सामने भी अपने कामकाज का हिसाब जनता के सामने रखने की चुनौती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून–व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, निवेश, धार्मिक पर्यटन और सरकारी भर्तियों को अपनी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत करती रही है।सरकार के मार्च 2026 में जारी नौ वर्ष के उपलब्धि दस्तावेज के अनुसार, उसके कार्यकाल में नौ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने अगस्त 2026 में यह संख्या 9.30 लाख से अधिक बताई थी। सरकार के अनुसार पुलिस विभाग में 2.19 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की गई है। ये सरकारी दावे हैं, जिनका आकलन नियुक्तियों की वास्तविक संख्या, नियमित और संविदा पदों के अंतर तथा रोजगार की गुणवत्ता के आधार पर होना चाहिए। सरकार ने एक्सप्रेसवे, सड़क, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक निवेश और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी विस्तार का दावा किया है। महाकुंभ 2025, अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के प्रयासों को विकास के प्रमुख उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हालांकि विकास का मूल्यांकन केवल बड़ी परियोजनाओं और निवेश सम्मेलनों से नहीं हो सकता। यह भी देखना होगा कि निवेश प्रस्तावों में से कितने धरातल पर उतरे, कितने लोगों को स्थायी रोजगार मिला और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का लाभ कितनी समानता से पहुंचा।

'रोजगाररू दोनों दलों के सामने सबसे बड़ा सवाल'

उत्तर प्रदेश में युवाओं का रोजगार ऐसा विषय है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को जवाब देना होगा।सपा ने 2022 में 22 लाख रोजगार का वादा किया था और अब 2027 के लिए 25 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य रखा है। दूसरी ओर योगी सरकार नौ लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियों का दावा कर रही है। इन दोनों आंकड़ों की सीधी तुलना उचित नहीं होगी, क्योंकि एक चुनावी वादा है और दूसरा सरकार की ओर से बताई गई नियुक्तियों की संख्या।फिर भी असली सवाल रोजगार की प्रकृति का है। कितनी नौकरियां नियमित हैं? कितने पद संविदा पर हैं? कितनी भर्तियां लंबित हैं? निजी क्षेत्र में रोजगार की गुणवत्ता और वेतन का स्तर क्या है? युवाओं को इन सवालों के स्पष्ट जवाब चाहिए।सपा का पांच हजार रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता तत्काल आर्थिक सहायता का प्रस्ताव है, लेकिन भत्ता स्थायी रोजगार का विकल्प नहीं हो सकता। वहीं सरकार की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता के दावे तभी सार्थक होंगे, जब प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर नियमित हो, पेपर लीक जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण हो और चयनित अभ्यर्थियों को समय पर नियुक्ति मिले।

'सामाजिक न्याय और पीडीएरू प्रतिनिधित्व बनाम वास्तविक सशक्तीकरण'

नए घोषणापत्र में जाति आधारित जनगणना और सरकारी ठेकों में पीडीए वर्गों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव विशेष महत्व रखता है। सपा का कहना है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि आर्थिक संसाधनों और निर्णय प्रक्रिया में भी भागीदारी मिलनी चाहिए।यह बहस संविधान में समानता, सामाजिक न्याय और आरक्षण की व्यवस्था से जुड़ी हुई है। हालांकि सरकारी ठेकों में प्रस्तावित 50 प्रतिशत हिस्सेदारी का कानूनी आधार, पात्रता, आरक्षण की श्रेणियां, छोटे उद्यमियों की भागीदारी और वित्तीय सीमा स्पष्ट करना आवश्यक होगा। इसे लागू करने के लिए विस्तृत नीति और संवैधानिक परीक्षण की भी जरूरत पड़ सकती है।वहीं भाजपा सरकार की ओर से महिला स्वयं सहायता समूहों, छात्रवृत्ति, सामाजिक पेंशन और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को अपनी उपलब्धियों में गिनाया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का दावा किया गया है। ऐसे में वास्तविक बहस यह होनी चाहिए कि इन योजनाओं से महिलाओं की आय, आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता में कितना बदलाव आया है। सामाजिक न्याय केवल घोषणाओं या जातीय समीकरणों से पूरा नहीं होगा। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रशासनिक भागीदारी और भेदभाव से सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

'किसानरू कर्जमाफी, एमएसपी और गन्ना भुगतान का पुराना सवाल'

उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसान हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। सपा ने 2022 में सभी फसलों पर एमएसपी, किसानों को 2025 तक कर्जमुक्त करने, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और किसान पेंशन का वादा किया था। नए घोषणापत्र में भी कृषि ऋण माफी, एमएसपी की कानूनी गारंटी, गन्ने का 24 घंटे में भुगतान और किसान पेंशन जैसे प्रस्ताव शामिल किए गए हैं।

दूसरी ओर योगी सरकार का दावा है कि 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 2.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं और कृषि उत्पादन में वृद्धि को भी अपनी उपलब्धियों में शामिल किया है। लेकिन किसान की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन केवल कुल भुगतान से नहीं होना चाहिए। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान, छोटे किसानों की लागत, खाद–बीज की उपलब्धता, फसल बीमा के दावे और बाजार में उपज का उचित मूल्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।सपा को अपनी ऋणमाफी और एमएसपी योजनाओं की वित्तीय रूपरेखा बतानी होगी, जबकि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसान को सरकारी आंकड़ों से आगे वास्तविक लाभ मिल रहा है।

'बिजली और पुरानी पेंशनरू लोकलुभावन वादे या आर्थिक जिम्मेदारी?'

300 यूनिट मुफ्त घरेलू बिजली का वादा सपा ने 2022 में भी किया था और अब इसे फिर से प्रमुखता दी गई है। इसके साथ किसानों को मुफ्त सिंचाई बिजली देने की बात भी सामने आई है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का प्रस्ताव भी सरकारी कर्मचारियों के बीच महत्वपूर्ण बहस का विषय बन सकता है।लेकिन इन योजनाओं की लागत कम नहीं होगी। चै स्महपेसंजपअम त्मेमंतबी के उत्तर प्रदेश बजट विश्लेषण 2026–27 के अनुसार राज्य का कुल बजट परिव्यय लगभग 9.13 लाख करोड़ रुपये है और राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का तीन प्रतिशत अनुमानित है। बिजली वितरण कंपनियों का मार्च 2025 तक संचित घाटा करीब एक लाख करोड़ रुपये बताया गया है। इस परिस्थिति में मुफ्त बिजली, किसान ऋणमाफी और पुरानी पेंशन जैसी योजनाओं को लागू करने के लिए स्पष्ट वित्तीय स्रोत बताना जरूरी होगा। सवाल यह नहीं कि जनता को राहत क्यों दी जाए, बल्कि यह है कि राहत का खर्च किस मद से आएगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क तथा अन्य विकास कार्यों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

'कानून–व्यवस्थारू दावों के साथ जवाबदेही भी जरूरी'

योगी सरकार कानून–व्यवस्था को अपनी प्रमुख उपलब्धि बताती है। पुलिस आधुनिकीकरण, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई को सरकार अपनी नीति का हिस्सा बताती रही है।दूसरी ओर सपा ने नए घोषणापत्र में महिला सुरक्षा, त्वरित न्याय, फास्ट ट्रैक अदालतों और पुलिस व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की बात कही है। अखिलेश यादव ने अपराध, माफिया गतिविधियों और महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर कठोर कार्रवाई का प्रस्ताव रखा ह ै। इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप से आगे बढ़कर अपराध के आंकड़ों, दोषसिद्धि दर, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, लंबित मुकदमों और पुलिस में रिक्त पदों का तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। कानून का राज किसी एक दल का चुनावी नारा नहीं, बल्कि शासन की अनिवार्य जिम्मेदारी है।

'घोषणापत्र में सबसे जरूरी सवालरू समयसीमा और बजट कहां है?'

सपा के नए घोषणापत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन की रूपरेखा पर स्पष्टता आवश्यक है।25 लाख सरकारी नौकरियों के लिए कितने वर्ष की समयसीमा होगी?पांच हजार रुपये बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्रता और लाभार्थियों की संख्या क्या होगी?40 हजार रुपये की वार्षिक सहायता किन महिलाओं और परिवारों को मिलेगी?10 लाख रुपये के स्वास्थ्य कवर का वित्तपोषण किस प्रकार होगा?50 प्रतिशत सरकारी ठेका आरक्षण का कानूनी और प्रशासनिक स्वरूप क्या होगा?पुरानी पेंशन बहाली का राज्य के बजट पर कितना प्रभाव पड़ेगा?किसानों की ऋणमाफी और एमएसपी गारंटी के लिए कितनी धनराशि निर्धारित होगी?इसी तरह मौजूदा सरकार को भी अपनी उपलब्धियों के साथ लंबित भर्तियों, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा की गुणवत्ता और बिजली वितरण व्यवस्था की चुनौतियों का जवाब देना चाहिए।

:निष्कर्षः चुनावी वादों से आगे जनता को चाहिए काम का हिसाब'

उत्तर प्रदेश का 2027 विधानसभा चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, बल्कि विकास के अलग–अलग मॉडलों और शासन की प्राथमिकताओं पर भी बहस का अवसर होगा। अखिलेश यादव का नया घोषणापत्र सामाजिक न्याय, रोजगार और आर्थिक भागीदारी को केंद्र में रखता है, जबकि योगी सरकार अपने नौ वर्षों के कार्यकाल में बुनियादी ढांचे, कानून–व्यवस्था, निवेश और सरकारी नियुक्तियों को अपनी उपलब्धियों के रूप में सामने रख रही है।दोनों पक्षों के दावों का मूल्यांकन तथ्यों, बजट और जमीन पर हुए काम के आधार पर होना चाहिए। केवल घोषणाओं से जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता और केवल उपलब्धियों के प्रचार से सभी समस्याओं का समाधान साबित नहीं होता।मतदाता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि किस दल ने क्या वादा किया, सत्ता में रहने पर क्या किया और भविष्य की योजनाओं को लागू करने के लिए उसके पास क्या ठोस व्यवस्था है।

'परवेज आलम
पत्रकार/सामाजिक विचारक एवं स्तंभकार'

मुट्ठी में दुनिया और छूटता हाथ!

कविता धर्माधिकारी

आज इंसान के हाथ में पूरी दुनिया है। एक छोटे से मोबाइल में हजारों किताबें हैं, लाखों जानकारियां हैं, मनोरंजन के अनगिनत साधन हैं और सात समंदर पार बैठे व्यक्ति से बात करने की सुविधा है, लेकिन एक अजीब विडंबना देखिए, दुनिया से जुड़ता जा रहा इंसान अपने ही घर में बैठे लोगों से दूर होता जा रहा है। कभी घरों में शाम होते ही रौनक हुआ करती थी। कोई दिनभर की कहानी सुनाता था, कोई अपनी परेशानी बताता था, तो कोई बिना किसी खास वजह के हंसी–मजाक कर लिया करता था। घर के आंगन में बैठकर चाय पीना भी एक उत्सव हुआ करता था। आज वही आंगन सूना है। बैठक में लोग मौजूद हैं, लेकिन सबकी दुनिया अलग–अलग मोबाइल स्क्रीन में कैद है। क्या सचमुच हमने तरक्की कर ली है या तरक्की की दौड़ में जीने का सलीका ही भूल गए हैं? आज मां अपने बेटे को आवाज लगाती है, बेटा मोबाइल में व्यस्त है। पिता अपनी बात कहना चाहते हैं, बेटी ऑनलाइन दुनिया में मशगूल है। पति–पत्नी एक ही कमरे में बैठे हैं, मगर बातचीत किसी तीसरे माध्यम से हो रही है। घर में चार लोग हैं, चार मोबाइल हैं और चारों की दुनिया अलग–अलग है। कभी बच्चे दादा–दादी से कहानियां सुनकर बड़े होते थे। आज कहानियां मोबाइल सुनाता है और दादा–दादी बच्चों का इंतजार करते रह जाते हैं। तकनीक ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार और संचार के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति ने जीवन आसान बनाया है, लेकिन सवाल तकनीक के विरोध का नहीं, बल्कि उसके गुलाम बन जाने का है। मोबाइल हमारा सेवक था, हमने उसे अपना मालिक बना लिया। आज सोशल मीडिया पर हजारों मित्र हैं, लेकिन मुसीबत के समय कंधा देने वाला एक मित्र ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जन्मदिन पर सैकड़ों शुभकामनाएं आती हैं, मगर बीमारी में हाल पूछने वाले गिने–चुने लोग ही होते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी जरूरत समय है और आज इंसान के पास समय ही नहीं है। मां–बाप बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे कपड़े और बेहतर भविष्य देने के लिए दिन–रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्या बच्चों को सिर्फ सुविधाएं चाहिए? उन्हें माता–पिता का समय भी चाहिए। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनकी बात बिना टोके सुने, उनकी असफलता पर डांटने के बजाय उनका हौसला बढ़ाए। इसी तरह बुजुर्गों को महंगे उपहारों से ज्यादा दो पल का अपनापन चाहिए। याद रखिए, बुजुर्गों को अकेलापन उम्र नहीं, अपनों की व्यस्तता देती है। आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम ऑनलाइन दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन घर में किसी अपने की पुकार सुनने में देर कर देते हैं। किसी अनजान व्यक्ति की पोस्ट पर टिप्पणी करने के लिए हमारे पास समय है, मगर पिता की पुरानी कहानी सुनने के लिए समय नहीं। किसी की तस्वीर पर दिल वाला निशान लगाने में हमें एक सेकंड लगता है, मगर अपने जीवनसाथी की उदासी समझने में कई दिन लग जाते हैं। हमें लाइक की संख्या याद रहती है, लेकिन अपनों की आंखों में छिपी उदासी दिखाई नहीं देती। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि मोबाइल छोड़ दिया जाए या तकनीक से दूरी बना ली जाए। तकनीक आज की जरूरत है और आने वाले समय की ताकत भी। जरूरत केवल इतनी है कि हम तकनीक को अपने जीवन का उद्देश्य न बना लें। बच्चों को मोबाइल देने से पहले उन्हें परिवार के साथ बैठना सिखाएं। बुजुर्गों को आधुनिकता से दूर करने के बजाय उन्हें नई तकनीक से जोड़ें। परिवार में प्रतिदिन कुछ समय ऐसा हो, जब कोई मोबाइल न हो, कोई स्क्रीन न हो, केवल बातचीत हो। सप्ताह में एक दिन परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। बच्चों से पूछें कि उनके मन में क्या चल रहा है। माता–पिता से उनके पुराने दिनों की बात सुनें। जीवनसाथी से बिना किसी काम के बात करें। छोटी–छोटी कोशिशें ही बड़े रिश्तों को बचाती हैं। हमें यह भी समझना होगा कि आने वाली पीढ़ी हमें देखकर ही सीखेगी। यदि माता–पिता हर समय मोबाइल में व्यस्त रहेंगे तो बच्चों से मोबाइल छोड़ने की अपेक्षा कैसे करेंगे? यदि घर में बातचीत की जगह स्क्रीन ले लेगा तो बच्चों में संवेदनाएं कैसे विकसित होंगी?



आपत्तियों और पुलिस जांच के बाद बेंगलुरु में पाकिस्तानी धारावाहिक 'दर-ए-नजात' की दो स्पेशल स्क्रीनिंग रद्द, देशभर में पाक कंटेंट पर तेज हुई बहस

> इस कार्यक्रम का प्रचार बेंगलुरु में इस ड्रामा की पहली स्क्रीनिंग के तौर पर किया गया था। इसमें ड्रामा के ३४वें और ३५वें एपिसोड दिखाए जाने थे, जिसके बाद फारसी और अरबी व्यंजनों वाला डिनर रखा गया था। दूसरी स्क्रीनिंग श्द स्टार क्लबश् द्वारा ५ दिसंबर को एक प्राइवेट थिएटर में आयोजित की जानी थी।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पाकिस्तानी टेलीविजन धारावाहिक 'दर–ए–नजात' (क्त–म–छरंज) की प्रस्तावित दो प्राइवेट स्क्रीनिंग को विभिन्न वर्गों से उठी आपत्तियों और पुलिस जांच के बाद रद्द कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर इन आयोजनों के प्रचार पोस्टर सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया था, जिसके चलते आयोजकों ने दोनों कार्यक्रमों को निरस्त करने का निर्णय लिया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब देशभर में पाकिस्तानी वेब सीरीज और मनोरंजन सामग्री के प्रसारण को लेकर फिल्म संगठनों का विरोध तेज हो गया है। इन स्क्रीनिंग का प्रचार सोशल मीडिया पर पोस्टर के जरिए किया गया था। इनमें से एक आयोजन द ब्लूम सोसाइटी सिस्टर्स क्लब द्वारा किया गया था, जो 28 नवंबर को फ्रेजर टाउन के शीशकबाब में होने वाला था। इस कार्यक्रम का प्रचार बेंगलुरु में इस ड्रामा की पहली स्क्रीनिंग के तौर पर किया गया था। इसमें ड्रामा के 34वें और 35वें एपिसोड दिखाए जाने थे, जिसके बाद फारसी और अरबी व्यंजनों वाला डिनर रखा गया था। दूसरी स्क्रीनिंग श्द स्टार क्लबश् द्वारा 5 दिसंबर को एक प्राइवेट थिएटर में आयोजित की जानी थी। दोनों कार्यक्रम शाम 6 बजे होने वाले थे। इन प्रस्तावित स्क्रीनिंग पर सवाल उठने के बाद मामला जांच के दायरे में आ गया। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त आर. हितेन्द्र ने पुष्टि की कि पुलिस ने इस मामले की जांच की है। उन्होंने बताया कि जांच के बाद, दोनों कार्यक्रमों के आयोजकों ने स्क्रीनिंग रद्द करने के अपने फैसले की पुष्टि कर दी है। शीशकबाब के एक प्रतिनिधि ने भी पुष्टि की कि 28 नवंबर का कार्यक्रम अब नहीं होगा। हालांकि, इसे रद्द करने का कोई खास कारण नहीं बताया गया। द स्टार क्लब की स्क्रीनिंग के आयोजक ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल परिवार के सदस्यों और करीबी परिचितों के लिए था। कार्यक्रम रद्द करने के फैसले पर उन्होंने कहा, हमने कार्यक्रम रद्द कर दिया है। हालांकि, यह केवल परिवार और करीबी लोगों के लिए ही था। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया है कि वह पाकिस्तान की आने वाली नेटफ्लिक्स सीरीज बच्चे हैं संग समेट लो को भारत में स्ट्रीम होने से रोके। फिल्म वर्कर्स संगठन ने अन्य व्ज्ज प्लेटफॉर्म्स से भी अपील की है कि वे देश में पाकिस्तानी कंटेंट न दिखाएं। इस सीरीज को नेटफ्लिक्स की मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका टीम ने तैयार किया है और इसका प्रीमियर 4 दिसंबर को होना है। मंगलवार को, ।ष्ब्। ने सरकार से मांग की कि वह यह सुनिश्चित करे कि यह शो नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज न हो। इसमें भारतीय टेलीविजन, OTT प्लेटफॉर्म और सिनेमा पर पाकिस्तानी कंटेंट, कलाकारों और प्रोडक्शंस पर रोक लगाने के लिए एक स्थायी कानून की मांग की गई है। एसोसिएशन ने अपने पत्र में कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी शो और फिल्मों से दूर रहने को कहा है। फिल्म वर्कर्स संगठन ने लिखा, ष्हमने सबसे कड़ी सजा वाले एक मजबूत और स्थायी कानून की मांग की है। हम नेटफ्लिक्स इंडिया और सभी OTT प्लेटफॉर्म से अपील करते हैं कि वे भारत में कभी भी कोई पाकिस्तानी कंटेंट न दिखाएं। उन्होंने आगे कहा कि श्पाकिस्तान एक आतंकवादी देश था, है और रहेगा। भारतीय स्क्रीन पर इसके शो, फिल्मों, गानों, पॉडकास्ट और किसी भी अन्य कंटेंट के लिए कोई जगह नहीं है। एसोसिएशन ने मई 2025 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एक एडवाइजरी का भी जिक्र किया। इस एडवाइजरी में भारत में काम कर रहे व्ज्ज प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग सेवाओं और अन्य मध्यस्थों से कहा गया था कि वे पाकिस्तान से आने वाले कंटेंट को दिखाना बंद करें। ICWA ने पुलवामा और पहलगाम हमलों के बाद पाकिस्तानी कलाकारों और कंटेंट पर लगाई गई पाबंदियों का हवाला दिया। उनका तर्क है कि भारत में बचे हैं संग समेट लो को रिलीज करना मंत्रालय की एडवाइजरी की भावना के खिलाफ होगा। पत्र में कहा गया है, पुलवामा हमले के बाद, AICWA ने भारतीय फिल्म उद्योग में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

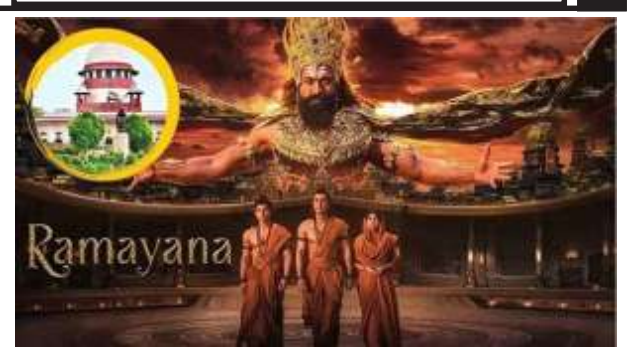

अपनी फिल्म अपने तरीके से बनाएं.. . रामायण विवाद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की दोटूक, सुनवाई से इनकार, कहा, कोर्ट का समय बर्बाद न करें

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रामायण महाकाव्य पर बनी एक फिल्म के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिल्म पहले ही सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की बेंच – जिसमें जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे– ने यह टिप्पणी तब की, जब याचिकाकर्ता के वकील ने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया कि फिल्म में महाकाव्य को तोड़–मरोड़ कर पेश किया गया है। यह देखते हुए कि फिल्म पहले से ही सिनेमाघरों में चल रही है, सीजेआई ने कहा कि जो लोग इसे देखना चाहते थे, उन्हें ऐसा करने का मौका पहले ही मिल चुका है। सीजेआई ने कहा, फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है। जो लोग इसे देखना चाहते थे, वे इसे देख चुके हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि फिल्म में कई तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसका असर नई पीढ़ी पर पड़ सकता है। हालांकि, बेंच इस दलील से सहमत नहीं हुई। आपत्ति का जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि फिल्म निर्माता महाकाव्य को अपने नजरिए से पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं और अगर किसी की सोच अलग है, तो वे अपने रचनात्मक कार्यों के जरिए उसे सामने ला सकते हैं। सीजेआई कांत ने टिप्पणी की, उन्होंने फिल्म को अपनी समझ के अनुसार बनाया है। आप अपनी फिल्म अपने तरीके से बनाएं। कोर्ट का समय बर्बाद न करें। अगर महाकाव्य को लेकर आपकी कोई अलग राय है, तो आप उस राय पर अपनी फिल्म बना सकते हैं। इस तरह, सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया। रामायण पार्ट 1 का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है और इसे नमित मल्होत्रा घ्ने प्रोड्यूस किया है। यह प्राचीन भारतीय महाकाव्य पर आधारित दो भागों वाली फिल्म का पहला हिस्सा है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में और सनी देओल हनुमान के रूप में नजर आएंगे। अनुपम खेर जटायु को अपनी आवाज देंगे। जटायु एक दिव्य पक्षी है जो कहानी में अहम भूमिका निभाता हैय वह रावण द्वारा अपहरण की गई सीता को बचाने की कोशिश करता है। अन्य मुख्य भूमिकाओं में अरुण गोविल, लारा दत्ता और रकुल प्रीत सिंह शामिल हैं।

बम की धमकी के बाद एक्शन में मुंबई पुलिस, दिलजीत के शो के लिए 500 से ज्यादा जवान तैनात



अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को होने वाले अभिनेता–गायक दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए मुंबई पुलिस के 500 से ज्यादा जवानों को महालक्ष्मी रेसकोर्स में तैनात किया जाएगा। यह कदम एक धमकी भरे ईमेल के बाद उठाया गया है, जिसमें कार्यक्रम स्थल और मेट्रो स्टेशनों पर हमले की चेतावनी दी गई थी। उन्होंने बताया कि बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (बीडीडीएस) की टीमों ने कार्यक्रम स्थल की जांच कर ली है। साथ ही, अब प्रवेश के समय तीन की बजाय सभी पांच गेटों पर चेकिंग की जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस की मदद के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी स्टाफ को भी तैनात किया गया है। गुरुवार को– जो कि 26/11 के भयानक आतंकी हमलों की बरसी भी है–एक ईमेल मिला, जिसमें मेयर कार्यालय, मेट्रो स्टेशनों और दोसांझ के कॉन्सर्ट में धमाके करने, ग्रेनेड से हमला करने और आईईडी लगाने की धमकी दी गई थी। यह ईमेल हन्ना मेलर नाम की एक व्यक्ति ने भेजा था। इसमें खालिस्तान और 1984 के सिख–विरोधी दंगों का जिक्र था, साथ ही दोसांझ और इस कार्यक्रम से जुड़े लोगों को हिंसा की धमकी भी दी गई थी। इस धमकी को देखते हुए, मुंबई पुलिस ने लगभग 200 कांस्टेबल, 150 महिला कांस्टेबल और 75 अधिकारियों को तैनात किया है। इसके अलावा, गायक के आसपास सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर डॉग स्क्वॉड और एंटी–नारकोटिक्स सेल (एएनसी) की टीम भी तैनात रहेगी। उन्होंने बताया कि रेसकोर्स के आसपास 500 से 700 मीटर के दायरे को नो–कार जोन बनाया जाएगा और कार्यक्रम स्थल पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, अभी तक किसी रास्ते को डायवर्ट करने की घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आयोजकों को निर्देश दिया गया है कि वे गायक के होटल या उनके आने के समय के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक न करें। इस बीच, आयोजकों ने महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाले कॉन्सर्ट के अंदर किसी भी तरह के पोस्टर, बैनर, साइन और झंडे लाने पर रोक लगा दी है। यह कॉन्सर्ट दोसांझ के रुपे ऑरा इंडिया टूर 2026 का हिस्सा है।



दुल्हन बनीं मिमी चक्रवर्ती सोशल मीडिया पर शेयर की शादी की खूबसूरत तस्वीरें

बंगाली फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस और नेता मिमी चक्रवर्ती ने शादी कर ली है। उन्होंने 26 नवंबर को एक निजी समारोह में सिद्धार्थ दत्ता के साथ सात फेरे लिए। शादी के बाद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की पहली तस्वीरें शेयर की हैं। हालांकि, उन्होंने अपने पति का चेहरा और पहचान सार्वजनिक नहीं की, लेकिन उनके नाम सिद्धार्थ दत्ता होने की पुष्टि की है। बंगाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिद्धार्थ पेशे से मरीन इंजीनियर हैं। मिमी चक्रवर्ती ने गुरुवार को अपनी शादी के बाद इंस्टाग्राम पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं। एक तस्वीर में मिमी और सिद्धार्थ अपनी शादी की अंगूठियां दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरी तस्वीर में दोनों अंगूठियां पहनाने के बाद एक–दूसरे को गले लगाते दिख रहे हैं। शादी के मौके पर मिमी और सिद्धार्थ ने क्रीम और सुनहरे रंग के कपड़े पहने थे। एक तस्वीर में मिमी सिद्धार्थ को अंगूठी पहनाती नजर आ रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में दोनों शादी का रजिस्ट्रेशन कराते दिखाई दे रहे हैं। एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में सिर्फ दिल वाले इमोजी लगाए हैं। उनकी शादी की तस्वीरें सामने आते ही फैंस और चाहने वालों ने उन्हें बधाइयां देनी शुरू कर दीं।

परिवार और करीबी दोस्तों के बीच हुई शादी

आनंद बाजार पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक, मिमी और सिद्धार्थ ने गुरुवार शाम दक्षिण कोलकाता में एक निजी समारोह में शादी की। इस मौके पर दोनों के परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त मौजूद थे। शादी से पहले एक्ट्रेस त्रिमिला भट्टाचार्य ने मीडिया से बातचीत में बताया था कि वह सिद्धार्थ की भाभी हैं और उनकी शादी सिद्धार्थ के बड़े भाई से हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि सिद्धार्थ पेशे से मरीन इंजीनियर हैं। त्रिमिला ने दोनों की जोड़ी की तारीफ करते हुए कहा, ष्दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मिमी को काफी अच्छी तरह जानने लगी हूं। वह बहुत अच्छी इंसान हैं और अपनी बात बेहद अच्छे तरीके से रखती हैं। उनका पूरा परिवार बहुत प्यारा है।



न महंगे गहने, न कोई बड़ा तोहफा...9 साल के बेटे ने जन्मदिन पर दिया ऐसा गिफ्ट छलक पड़े कश्मीरा के आंसू, सुनीता भी हुई खुश

बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने कश्मीरा शाह के बेटे द्वारा दिए गए खास गिफ्ट को देखकर बहुत प्यारा है कहा। गुरुवार को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, कश्मीरा ने एक खास पल साझा किया, जिसमें उनके 9 साल के बेटे ने उन्हें प्री–बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक खूबसूरत चूड़ी दी। लाफ्टर शेफ की कंटेस्टेंट कश्मीरा ने अपने बेटे के चूड़ी देने की कुछ झलकियां शेयर करते हुए कहा कि यह गहना हमेशा उनके दिल के बहुत करीब रहेगा। उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल पर लिखा, इस छोटी सी, सिंपल चूड़ी को अपनी कलाई पर पहनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा 9 साल का प्यारा बेटा मेरे लिए यह प्री–बर्थडे गिफ्ट लेकर आया। उसने मुझे प्यार की यह निशानी दी, जिसने मेरा दिल पिघला दिया। मेरे पास अब तक जितने भी गहने रहे हैं, उनमेंसे कोई भी मेरे बेटे द्वारा पूरे प्यार से चुने गए इस गिफ्ट की बराबरी नहीं कर सकता। उसकी मां होने पर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूं। इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनीता आहूजा ने कमेंट किया, बहुत प्यारा है मेरे लाल और साथ में हाथ जोड़ने और किस करने वाले इमोजी भी लगाए। लंबे समय तक दूरियां रहने के बाद, अब कश्मीरा और सुनीता के बीच काफी अच्छे रिश्ते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, गोविंदा के साथ तलाक की चर्चाओं के बीच कश्मीरा को सुनीता आहूजा के समर्थन में भी खड़ा देखा गया था। सितंबर में, जब गोविंदा की कथित गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री कोमल रानी स्वर्णकार ने सुनीता को चालाक औरत कहा और आरोप लगाया कि उनके आने से पहले ही गोविंदा और सुनीता के बीच समस्याएं चल रही थीं, तब कश्मीरा ने सवाल उठाया कि कोमल को अपने को–स्टार की जिंदगी की इतनी निजी बातें कैसे पता चलीं। उन्होंने लिखा, अपने करियर की शुरुआत से लेकर अब तक, 30 सालों और कुल 50 फिल्मों में, मेरे किसी भी को–स्टार को मेरी निजी जिंदगी या भावनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने सिर्फ उसी इंसान को सब कुछ बताया, जिससे मैंने शादी की –कृष्णा 30। मैंने काम की जगह पर कभी ऐसा रिश्ता नहीं देखा, जहाँ कोई सहकर्मी इतनी निजी बातें जानता हो। बता दें कि कश्मीरा की शादी गोविंदा के भतीजे कृष्णा अभिषेक से हुई है। सुनीता, कृष्णा की मामी हैं।



टमाटर का ताजापन कभी न हो जाए कम, जानें स्टोरिंग के 8 एक्सपर्ट टिप्स!

टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसे घरों में हर रोज इस्तेमाल किया जाता है। सलाद, सूप, चटनी, करी, और अन्य कई व्यंजनों में टमाटर का उपयोग होता है। हालांकि, यह जल्दी खराब होने वाली चीज है और इसे सही तरीके से स्टोर न करने पर इसकी ताजगी कम हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि टमाटर लंबे समय तक ताजे रहें, तो नीचे लिखे 8 टिप्स को ध्यान में रखें। ये टिप्स न केवल आपके टमाटरों की ताजगी बनाए रखने में मदद करेंगे, बल्कि वे उनका स्वाद भी बेहतर बनाए रखेंगे।

सही टेम्परेचर पर रखे

टमाटर को फ्रिज में रखना आमतौर पर गलत समझा जाता है। यदि आप टमाटरों को फ्रिज में रखेंगे, तो उनका स्वाद और बनावट बिगड़ सकते हैं। टमाटर को हमेशा रूम टेम्परेचर पर रखें, लेकिन यह ध्यान रखें कि टेम्परेचर बहुत अधिक न हो। अगर मौसम गर्म है, तो आप उन्हें ठंडी और सूखी जगह पर रख सकते हैं। टमाटरों को ठंडे जगह पर रखने से उनकी ताजगी बनी रहती है, और वे जल्दी सड़ते नही है।

कागज की तौलिया में लपेटें

टमाटर को रखने के समय ज्यादा नमी से बचाना बहुत जरूरी है। टमाटरों को कागज की तौलिया में लपेटने से वे नमी को सोख लेते हैं, जिससे सड़ने और खराब होने के चांस कम हो जाते है। यह बहूत उपयोगी होता है जब आप टमाटरों को एक साथ रखते हैं, क्योंकि नमी से उन पर जल्दी फंगस लग सकती है। कागज की तौलिया ज्यादा नमी को सोख लेती है और चीजों को ताजा रखती है।

पके हुए और कच्चे टमाटरों को अलग रखें

जब आप टमाटर खरीदते हैं, तो ध्यान दें कि कुछ टमाटर पकने के लिए तैयार हो सकते हैं, जबकि कुछ कच्चे होते हैं। पके हुए और कच्चे टमाटरों को एक साथ रखने से उनका खराब होना जल्दी हो सकता है, क्योंकि पके हुए टमाटर कच्चे टमाटरों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए, इन दोनों को अलग–अलग रखें, ताकि दोनों की ताजगी बनी रहे। पके हुए टमाटरों को जल्द से जल्द उपयोग करें, जबकि कच्चे टमाटरों को कमरे के तापमान पर रखें ताकि वह पक सकें।

टमाटरों को एक–दूसरे के ऊपर न रखें

कभी भी टमाटरों को एक–दूसरे के ऊपर न रखें। एक दूसरे पर दबाव डालने से टमाटर जल्दी दब सकते हैं और उनकी बाहरी सतह पर दरारें पड़ सकती हैं, जो खराब होने का कारण बन सकती हैं। टमाटरों को हमेशा सपाट और एक–दूसरे से थोड़ी दूरी पर रखें। यदि आप एक कंटेनर में टमाटर रख रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि उनके ऊपर कोई भारी वस्तु न हो।

पत्तियां और टहनियां हटा दें

जब आप टमाटर लाते हैं, तो उनकी पत्तियांऔर टहनियां हटा दें। पत्तियाँ टमाटरों की नमी को अवशोषित कर सकती हैं और उनके सड़ने का कारण बन सकती हैं। इसलिए, टमाटरों को पत्तियां और टहनियां हटाकर स्टोर करें। इससे टमाटर ताजे रहते हैं और जल्दी खराब नहीं होते।

पानी से दूर रखें

टमाटर को पानी में भिगोने से बचें। पानी में भिगोने से टमाटर जल्दी सड़ सकते हैं और उनका स्वाद भी बिगड़ सकता है। हमेशा टमाटरों को सूखा रखें और सुनिश्चित करें कि उन पर कोई अतिरिक्त पानी न हो। जब आप टमाटरों को धोते हैं, तो उन्हें अच्छे से सुखा लें, ताकि पानी से उनका खराब होने का खतरा न हो।

चमकदार और बिना धब्बे वाले टमाटर चुनें

जब भी आप टमाटर खरीदने जाएं, तो कोशिश करें कि ताजे, चमकदार रंग के और बिना किसी धब्बे वाले टमाटर ही खरीदें। पुराने और खस्ता टमाटर जल्दी खराब हो जाते हैं। टमाटरों की त्वचा पर कोई भी निशान या धब्बे न हों, यह सुनिश्चित करें। यदि टमाटर पर किसी भी प्रकार का दाग या धब्बा दिखाई दे, तो वह खराब होने का संकेत हो सकता है, और ऐसे टमाटर को जल्द ही उपयोग कर लेना चाहिए। टमाटर को ताजगी बनाए रखने के लिए इन सरल लेकिन प्रभावी टिप्स का पालन करें। सही स्टोरिंग तकनीक के साथ आप अपने टमाटरों को लंबे समय तक ताजे रख सकते हैं और उनका स्वाद भी बनाए रख सकते हैं। इन टिप्स को अपनाकर आप न केवल टमाटरों की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, बल्कि उनका पोषण भी बरकरार रख सकते हैं।

क्या आप भी पित्त की पथरी से परेशान हैं? जानें इसके खतरनाक संकेत और बचने के उपाय



पित्त की पथरी एक आम समस्या है, जो शरीर के विभिन्न अंगों में बन सकती है, और समय के साथ गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। यह खासतौर पर पित्ताशय (गॉलब्लैडर) में बनती है और आमतौर पर पित्त में मौजूद तत्वों के जमा होने से बनती है। पित्त की पथरी का आकार रेत के दाने जितना छोटा हो सकता है या फिर गेंद जितना बड़ा भी हो सकता है। कुछ लोगों में एक पित्त की पथरी बनती है, जबकि दूसरों में कई पथरी एक साथ बन सकती हैं। इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों को समझना और समय रहते उपचार करना महत्वपूर्ण है।

पित्त की थैली में पथरी के शुरुआती संकेत

दाहिने हिस्से में दर्द

पित्त की पथरी होने पर पेट के दाहिने हिस्से में हल्का से लेकर तेज दर्द महसूस हो सकता है। यह दर्द खाने के बाद बढ़ सकता है और कभी–कभी यह दर्द पीठ और कंधे तक फैल सकता है।

भारीपन और अपच

पित्त की पथरी पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकती है, जिससे खाना खाने के बाद पेट में भारीपन, अपच, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इन लक्षणों को नजरअंदाज करना गंभीर हो सकता है, क्योंकि यह पित्त की पथरी की संभावना को बढ़ाता है।

मतली और उल्टी

पित्त की पथरी के कारण पित्त का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता, जिससे पेट में सूजन और पित्त के प्रवाह में समस्या उत्पन्न होती है। इस वजह से तला–भुना या मसालेदार खाना खाने के बाद अक्सर मतली और उल्टी हो सकती है।

पेट में सूजन और गड़बड़ी

पित्त की पथरी की वजह से पेट में हल्की या गंभीर सूजन हो सकती है। इसके साथ गैस, भारीपन और पाचन संबंधी समस्याएं जैसे कब्ज और पेट दर्द भी हो सकती हैं। कई बार यह लक्षण खाना न पचने पर भी होते हैं।

पेशाब के रंग में बदलाव

गालब्लैडर की पथरी के कारण पेशाब का रंग पीला हो सकता है, और कभी–कभी खून भी आ सकता है। इसके अलावा, बार–बार पेशाब आना भी पित्त की पथरी के गंभीर लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा, पित्त की पथरी के कारण थकान, कमजोरी, पीठ और पेट के साइड्स में दर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

कब जाएं डॉक्टर के पास?

अगर आपको उपरोक्त लक्षणों में से कोई भी महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। पित्त की पथरी का सही समय पर इलाज करने से इसकी जटिलताओं से बचा जा सकता है। इसके अलावा, अगर आपको पीलिया जैसी समस्या हो तो पित्त की पथरी की जांच करवाना जरूरी है।

पित्त की पथरी से बचाव के उपाय

भरपूर पानी पिएं

पानी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, और यह पित्त की पथरी के निर्माण को रोकने में भी मदद कर सकता है। पानी पित्तियों को पतला रखने में मदद करता है, जिससे पित्त की गाढ़ी बनावट नहीं होती। अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो पित्त में मौजूद घटक एकजुट होकर पथरी का रूप ले सकते हैं।

सामान्यतः एक दिन में 8–10 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है, जिससे शरीर में सही हाइड्रेशन बनी रहे और पित्ताशय की समस्याओं से बचा जा सके।

तला–भुना और मसालेदार भोजन से बचें

तला–भुना और मसालेदार भोजन पाचन क्रिया को धीमा कर देता है और शरीर के भीतर अशुद्धि को बढ़ाता है। जब आप इन प्रकार के भोजन का अत्यधिक सेवन करते हैं, तो पित्ताशय में अतिरिक्त पित्त जमा होने लगता है, जिससे पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, यह आपके जिगर और आंतों पर दबाव डालकर पाचन समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए तला–भुना और अत्यधिक मसालेदार भोजन से बचना महत्वपूर्ण है, ताकि शरीर का पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता रहे।

खाना स्किप न करें

अगर आप नियमित रूप से भोजन नहीं करते हैं या खाना स्किप करते हैं, तो इसका सीधा असर पित्ताशय पर पड़ता है। खाना छोड़ने से पित्त का निर्माण अधिक होता है, जो बाद में पथरी में बदल सकता है। इससे पाचन प्रक्रिया असंतुलित हो जाती है और पेट में भारीपन, गैस, या अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, दिन में तीन मुख्य भोजन और दो स्नैक्स का सेवन करना चाहिए, ताकि पाचन तंत्र सही ढंग से काम करता रहे और पित्त की पथरी से बचाव हो सके।

वजन नियंत्रित रखें

अधिक वजन होना पित्त की पथरी बनने का एक बड़ा कारण हो सकता है। जब शरीर में अतिरिक्त वसा जमा होती है, तो यह पित्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकती है, जिससे पित्त की पथरी का निर्माण हो सकता है। वजन बढ़ने से शरीर में हार्मोनल असंतुलन भी हो सकता है, जो पित्त की पथरी के निर्माण को बढ़ावा देता है। इसलिए वजन को नियंत्रित रखना बेहद जरूरी है, और इसके लिए नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आवश्यक है।

फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ खाएं

फाइबर युक्त भोजन पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और पित्त की पथरी के निर्माण को रोक सकता है। ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, और बीजों में उच्च मात्रा में फाइबर होता है, जो पित्त के प्रवाह को नियमित रखता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है। फाइबर शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और पाचन को सही बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसलिए, अपनी डाइट में इन खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। इन उपायों का पालन करके आप पित्त की पथरी से बच सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बनाए रख सकते हैं।

ड्राई स्किन होंगी छूमंतर, बस इस तरह से घर पर बनाएं एलोवेरा बॉडी लोशन



विंटर सीजन में ड्राई स्किन से हम सभी परेशान रहते है। कितना भी ध्यान रखे लें स्किन का फिर सूखी त्वचा हो जाती है। हवा में नमी इतनी कम होती है कि स्किन ड्राई होने लगती है। स्किन को सॉफ्ट और मुलायम बनाने के लिए आपको महंगे–महंगे प्रोडक्ट्स लेने की कोई जरुरत नहीं है। अपनी स्किन मुलायम और चिकनी बनाने के लिए आप घर पर ही बॉडी लोशन बना सकते हैं। आइए आपको बताते हैं बॉडी लोशन बनाने का तरीका।

बॉडी लोशन बनाने के लिए सामग्री

– 1 कप नारियल तेल
– 1 कप एलोवेरा पत्ती
– लैवेंडर ऑयल की कुछ बूंदें
– लोबान ऑयल की कुछ बूंदें

एलोवेरा बॉडी लोशन कैसे बनाएं

ड्राई स्किन से छुटकारा पाने के लिए एलोवेरा बॉडी लोशन तैयार करते हैं। सबसे पहले एलोवेरा को काटकर साफ करें। एलोवेरा के कांटों और छिलकों को भी निकाल लें। फिर इसको जेल को निकालें। इसे जेल को गंदगी को साफ करने के लिए इसे पानी में धो लें। इसके बाद टिशू पेपर से एक्सट्रा पानी को निकाल दें। अब जेल को अच्छे ब्लेंड कर लीजिए। जब लोशन में हल्की और मक्खन जैसी कंसिस्टेंसी आ जाए तो इसमें लैवेंडर और लोबान मिलाएं। इसके बाद अच्छे से मिक्स करके अपने पसंदीदा एयर टाइट कंटेनर में इसे पैक करें। बॉडी लोशन तैयार करते है। इसको आपको 15–20 दिन के लिए आराम से रख सकते हैं। नहाने के तुरंत बंद इस लोशन को लगाए ताकी बेस्ट रिजल्ट मिले।



जल्द ही बनने जा रही है दुल्हन, तो अपने मेकअप किट में इन प्रोडकट्स को एड–ऑन करें

जीवन में शादी का दिन बेहद खास होता है। शादी का दिन जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर होता है, और हर दुल्हन अत्यधिक खर्च किए बिना सुंदर महसूस करने की हकदार है। हाई–एंड ब्राइडल मेकअप लुक हासिल करना महंगा नहीं है। सही बजट के अंदर बेहतरीन मेकअप प्रोड्क्टस होना जरुरी है। लंबे समय चलने वाले ये मेकअप उत्पाद बड़े–बेड ब्रांड को टक्कर देते हैं। फाउंडेशन से लेकर भारी मस्कारा और चमकते हाइलाइटर्स तक, ये किफायती विकल्प आपको मिल जाएंगे। आइए आपको इन बारे में बताते हैं।

जीरो ब्लेंड वेटलेस फाउंडेशन

कम बजट वाले मेकअप उत्पाद की तलाश में हैं, तो आपको बता दें कि, MARS का जोरो ब्लेंड फाउंडेशन ज्यादा महंगा नहीं है। यह मैट फिनिश प्रदान करता है। इसका हल्का, हाइड्रेटिंग फॉर्मूला आसानी से चेहरे पर फुल कवरेज देता है। इसे पूरे दिन लगा सकते है। चाहे आप नेचुरल या पूर्ण–कवरेज लुक पसंद करते हों, यह फाउंडेशन गर्मी और नमी में भी टिका रहता है, जिससे लंबे समय तक ताजगी बनी रहती है। हर भारतीय त्वचा टोन के अनुरूप इसे डिजाइन किया गया, यह ब्राइड के लिए एकदम सही विकल्प है। इसे आप ऑनलाइन या बाजार से भी खरीद सकते हैं।

मैट और सेट डुओ कॉम्पैक्ट

कम बजट में फ्लोलेस, कम चमक के साथ फिनिश वाला यह कॉम्पैक्ट दुल्हानों के लिए बेस्ट है। स्विस ब्यूटी मैट और सेट डुओ कॉम्पैक्ट बहुत जरूरी है। इस टू–इन–वन उत्पाद में स्मूथ, समान कवरेज के लिए एक कॉम्पैक्ट पाउडर और ब्राइटनिंग और टच–अप के लिए एक बेस्ट पाउडर है। हल्का और इजी ब्लेंड के साथ, यह एक सहज मैट फिनिश देता है, जो पूरे दिन बनी रहती है। यह प्रोडक्ट यात्रा के लिए बिल्कुल उपयुक्त, यह किफायती डुओ दुल्हन के मेकअप किट के लिए बेस्ट है।

बेक्ड हाइलाइटर

यह हाइलाइटर इनसाइट रिवोल्यूशनरी पैलेट ब्राइड के लिए काफी बढ़िया है। इसकी वेलवेट, सॉफ्ट बनावट सरलता से चेहरे पर फिनिश देती है। बस एक टच से ही स्किन को यह चमकदार बना देती है। यह काफी लंबे समय तक चलने वाला हाइलाइटर है। यह एकदम बजट–अनुकूल उत्पाद है।

होलोग्राफिक लिक्विड आईलाइनर

आजकल होलोग्राफिक आईलाइनर काफी ट्रेंड में है। इनको आप अपनी मेकअप किट में जरुर शामिल करें। यह आपकी आंखों को एक 3डी, मनोरम लुक देता है। बता दें कि, यह प्रोडक्ट वाटरप्रूफ है काफी लंबे समय तक चलता है। होलोग्राफिक लिक्विड आईलाइनर दुल्हन की सुंदरता को एक चमकदार फिनिश के साथ सामने लेकर आता है।

ग्लिटर पैलेट

Shryoan यूनाइटेड के ग्लिटर पैलेट के साथ अपनी आंखों का चमका सकते हैं! आंखों को आकर्षक लुक देने के लिए यह पैलेट आपका पसंदीदा बन जाएगा। क्योंकि यह प्रभावशाली, उच्च चमक वाले चमकदार टोन से भरा है। यह लंबे समय तक चलने वाला और लगाने में आसान है, जो इसे शादियों, पार्टियों और अन्य विशेष अवसरों को आकर्षक बनाने के लिए आदर्श बनाता है।

जसप्रीत बुमराह दोनों टीमों के बीच बड़ा अंतर, न्यूजीलैंड के क्रिस केर्न्स ने की तारीफ



न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर क्रिस केर्न्स ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दोनों टीमों के बीच एक निर्णायक अंतर बताया। उन्होंने कहा कि अगर बुमराह प्लेइंग इलेवन में शामिल हों, तो उस टीम की जीत की संभावना काफी बढ़ जाती है। 1989 से 2006 तक न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाले केर्न्स ने 8,273 रन बनाए (जिसमें नौ शतक शामिल हैं) और 420 विकेट लिए (जिसमें 14 बार एक पारी में पांच विकेट और एक बार मैच में दस विकेट लेना शामिल है)। उन्होंने न्यूजीलैंड और भारत के बीच चल रहे क्राइस्टचर्च टेस्ट के दौरान ।छप् से बात की; यह टेस्ट तय करेगा कि दो मैचों की इस सीरीज का विजेता कौन होगा। केर्न्स ने कहा कि मौजूदा न्यूज़ीलैंड टीम, हर खिलाड़ी की तुलना में भारतीय टीम से बेहतर है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जसप्रीत बुमराह दोनों टीमों के बीच बड़ा अंतर पैदा करते हैं और उन्हें अब तक के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बताया। 2000 में प्ब्ब चौंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली न्यूज़ीलैंड टीम का हिस्सा रहे इस दिग्गज खिलाड़ी ने कहा कि मुझे लगता है कि न्यूज़ीलैंड की टीम, हर खिलाड़ी की तुलना में, इस समय बेहतर है। लेकिन आपके पास जसप्रीत बुमराह हैं, जो किसी भी टीम के लिए बड़ा अंतर साबित हो सकते हैं। इसलिए, अगर वह आपकी टीम में खेल रहे हैं – जैसा कि अभी वह खेल रहे हैं – तो आपकी टीम हमेशा जीत की प्रबल दावेदार होगी। बुमराह अब तक के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। भारत के लिए 245 मैचों में 516 विकेट लेने वाले बुमराह, भारत के सबसे सफल तेज़ गेंदबाजों में से एक हैं और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों की सूची में आठवें स्थान पर हैं। केवल 54 टेस्ट मैचों में 20.09 की औसत से 239 विकेट लेने और अलग–अलग परिस्थितियों में 16 बार एक पारी में 5 विकेट लेने वाले बुमराह, पिछले कुछ वर्षों में एक टेस्ट टीम के रूप में भारत की सफलता में सबसे अहम खिलाड़ी रहे हैं। आजकल की पीढ़ी में तेज़ गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडरों की कमी और उन्हें होने वाली चोटों के बारे में बात करते हुए, केर्न्स ने कहा कि ऐसा ज्20ए और व्क्ए क्रिकेट के बदलते स्वरूप की वजह से हुआ है, जहाँ अब स्पिन गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उन्होंने इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी बेन स्टोक्स (जो अब संन्यास ले चुके हैं) को पिछली पीढ़ी के ष्शायद आखिरीष् असली तेज़ गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में बताया। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि तेज़ गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडरों की बात करें, तो बेन स्टोक्स शायद आखिरी खिलाड़ी थे। पांड्या भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि स्टोक्स पिछली पीढ़ी के एक सच्चे ऑलराउंडर थे। जब मैं एंड्रयू फ्लिंटॉफ, जैक कैलिस, शॉन पोलक या लांस क्लूजनर के साथ खेलता था, तो उनके खेलने के अंदाज़ में एक अलग बात होती थी।

क्राइस्टचर्च टेस्ट के डे 1 पर आकाशदीप बोले, गेंदबाजी में और बेहतर कर सकती थी टीम इंडिया

क्राइस्टचर्च में पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद, भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप ने कहा कि टीम गेंदबाजी में और बेहतर कर सकती थी। उन्होंने गेंदबाजी के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी बात की। क्राइस्टचर्च टेस्ट का पहला दिन काफी उतार–चढ़ाव भरा रहा। एक समय न्यूजीलैंड का स्कोर 184/5 था, लेकिन विकेटकीपर–बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल की अर्धशतकीय पारी और ग्लेन फिलिप्स के साथ उनकी नाबाद 62 रनों की साझेदारी की बदौलत, न्यूजीलैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 246/5 घ्ब्का स्कोर बना लिया। पहले सेशन में भारत को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन दूसरा सेशन पूरी तरह भारत के नाम रहा। न्यूजीलैंड का स्कोर 110/1 से गिरकर 110/4 हो गया, जिसमें से दो विकेट आकाश दीप ने लिए। आखिरी सेशन में भारत को सिर्फ एक विकेट मिला, जबकि इस दौरान उन्होंने 115 रन दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आकाश दीप ने बताया कि पिच नई थी, लेकिन नमी के कारण गेंद की रफ्तार धीमी हो गई थी, जिसकी वजह से बल्ले के किनारे (एज) से लगी गेंदें फील्डरों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही थीं। उन्होंने आगे कहा कि आज पिच काफी नई थी, जिससे हमें काफी मदद मिली। लेकिन पहले सेशन में नमी ज्यादा थी, इसलिए गेंद में उतनी रफ्तार नहीं थी और किनारे से लगी गेंदें फील्डरों तक नहीं पहुंच पा रही थीं। लंच के बाद हमने सही जगह पर गेंदबाजी करने पर ध्यान दिया। हमारी योजना सही एरिया में गेंद डालने और धैर्य के साथ खेलने की थी। हमने ऐसा ही किया और हमें तीन विकेट मिले। दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले इंडिया ए के लिए खेल चुके आकाश ने कहा कि अगर धूप पहले दिन की तरह ही बनी रहती है, तो विकेट और बेहतर हो जाएगा। टीम की कुल गेंदबाजी के बारे में उन्होंने कहा, ष्कुल मिलाकर यह काफी अच्छी रही, लेकिन हम और बेहतर कर सकते थे। फिर भी, मुझे लगता है कि यह ठीक है।ष् शुक्रवार को क्राइस्टचर्च में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन, टॉम ब्लंडेल और ग्लेन फिलिप्स के बीच हुई एक ठोस और नाबाद अर्धशतकीय साझेदारी ने न्यूजीलैंड को मिडिल–ऑर्डर के ढहने के बाद उबारा। दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 246/5 घ्ब्था। जब न्यूजीलैंड का स्कोर 184/5 हो गया था, तब ब्लंडेल (53′) और फिलिप्स (36′) ने मिलकर 62 रनों की नाबाद साझेदारी की। इससे मेजबान टीम ने बिना कोई और विकेट गंवाए दिन का खेल एक मजबूत स्थिति में समाप्त किया।



संक्षिप्त



विदेशी निवेशकों के लिए सेबी की नई तैयारी, FPI पंजीकरण अब 5 दिनों में होगा पूरा

सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने शुक्रवार को कहा कि बाजार नियामक का लक्ष्य डिजिटल कार्यप्रवाह और प्रणाली एकीकरण के माध्यम से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के पंजीकरण में लगने वाले समय को कई महीनों से घटाकर सिर्फ पांच कार्यदिवस करना है। उद्योग मंडल एसोचौम द्वारा आयोजित 17वें पूंजी बाजार सम्मेलन में पांडेय ने कहा कि नियामक ने एफपीआई के लिए अतिरिक्त खुलासा ढांचे को समाप्त करने का भी प्रस्ताव दिया है, जिससे भारत का नियामकीय रूपरेखा वैश्विक मानकों के और करीब आ जाएगा। पांडेय ने कहा, डिजिटल कार्यप्रवाह और प्रणाली एकीकरण के जरिये हमारा लक्ष्य एफपीआई के पंजीकरण समय को महीनों से घटाकर महज पांच कार्यदिवस तक लाना है। पिछले कुछ महीनों में सेबी ने एफपीआई के लिए अनुपालन के बोझ को कम करने को लेकर कई कदम उठाए हैं। स्वागत–एफआई भरोसेमंद विदेशी निवेशकों के लिए एकल खिड़की पहल है, जिसके तहत लगभग 740 एफपीआई पंजीकृत हो चुके हैं। इनकी कुल एफपीआई परिसंपत्तियों में लगभग 17 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा, स्वागत–एफआई भरोसेमंद और कम जोखिम वाले एफपीआई को एकल–खिड़की पहुंच, सरल अनुपालन और अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) की समीक्षा के लिए लंबी अवधि देता है। पांडेय ने कहा कि सेबी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के पास दाखिल किए जाने वाले विवरणों में दोहरे खुलासों को समाप्त करने के लिए सूचीबद्धता दायित्व और खुलासा आवश्यकताएं (एलओडीआर) रूपरेखा की व्यापक समीक्षा कर रहा है। नियामक एक ही अनुपालन चूक के लिए विभिन्न शेयर बाजारों द्वारा लगाए जाने वाले अलग–अलग जुर्माने के स्थान पर एकल जुर्माना व्यवस्था लागू करने की भी योजना बना रहा है।

नेस्ले इंडिया को EPFO से 36.36 लाख रुपये की देनदारी का नोटिस मिला

रोजमर्रा की जरूरत का सामान बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से 36.36 लाख रुपये की मांग का नोटिस मिला है। इसमें वर्ष 2012 से 2019 की अवधि के लिए 20 लाख रुपये से अधिक का हर्जाना भी शामिल है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में शुक्रवार को बताया कि ईपीएफओ के मैसूरु क्षेत्रीय कार्यालय ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 7क्यू



और 14बी के तहत यह नोटिस जारी किया है। नेस्ले इंडिया ने कहा, कंपनी को कर्मचारी भविष्य निधि के क्षेत्रीय कार्यालय से यह नोटिस प्राप्त हुआ। इसमें कुल 36,36,548 रुपये की मांग की गई है, जिसमें भविष्य निधि कोड के तहत वर्ष 2012 से 2019 की अवधि के लिए हर्जाने और जुर्माने के रूप में 20,09,516 रुपये शामिल हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया कि 26 नवंबर, 2026 को प्राप्त इस नोटिस का उसके वित्तीय प्रदर्शन, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 7क्यू के तहत नियोक्ता को बकाया राशि पर ब्याज देना होता है, जबकि धारा 14बी के तहत भविष्य निधि अंशदान और अन्य वैधानिक बकाया जमा करने में चूक के लिए हर्जाना वसूला जाता है। नेस्ले इंडिया देश की प्रमुख खाद्य एवं पेय पदार्थ कंपनियों में शामिल है। इसके प्रमुख ब्रांड में मैगी, नेस्कैफे, किटकैट, मिल्कमेड और एवरीडे शामिल हैं।

बजट से पहले CREDAI की मांग, Affordable Housing की सीमा बढ़ाकर 90 लाख करे सरकार

रियल एस्टेट कंपनियों के शीर्ष निकाय क्रेडाई ने अपनी बजट–पूर्व सिफारिशों में कम लागत वाली आवासीय संपत्तियों की मांग और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 90 लाख रुपये तक की कीमत वाले घरों को किफायती आवास श्रेणी में शामिल करने का सुझाव दिया है। फिलहाल 45 लाख रुपये तक की आवासीय इकाइयों को ही किफायती आवास माना जाता है। निर्माणाधीन फ्लैटों पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के पांच प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगता है। किफायती आवास पर बिना आईटीसी के एक प्रतिशत जीएसटी लागू है। तैयार हो चुकी इकाइयों पर कोई जीएसटी नहीं लिया जाता है। कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) ने आम बजट 2027–28 के लिए अपनी सिफारिशें सौंपी हैं। निकाय ने बाजार की मौजूदा वास्तविकताओं के अनुरूप किफायती आवास की परिभाषा में बदलाव की मांग की है। साथ ही उसने कुल नई पेशकश में नए किफायती घरों की आपूर्ति की हिस्सेदारी घटकर लगभग 20 प्रतिशत रह जाने पर चिंता जताई है, जो 2018 में 54 प्रतिशत थी। इस समस्या के समाधान के लिए संगठन ने जीएसटी, आयकर और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के मानदंडों में किफायती आवास की एक समान, क्षेत्रफल–आधारित परिभाषा का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत अधिसूचित महानगरों में 70 वर्ग मीटर, 10 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरी केंद्रों में 90 वर्ग मीटर तथा अन्य स्थानों पर 120 वर्ग मीटर की रेरा कारपेट क्षेत्र सीमा की सिफारिश की गई है। किफायती घरों पर कम जीएसटी लगता है, इसलिए मूल्य सीमा में बढ़ोतरी से उपभोक्ता मांग बढ़ेगी। किफायती घरों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्रेडाई ने मांग की है कि सरकार एक नई धारा 142ए के जरिये पूर्ववर्ती धारा 80–आईबीए के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन को फिर से लागू करे।

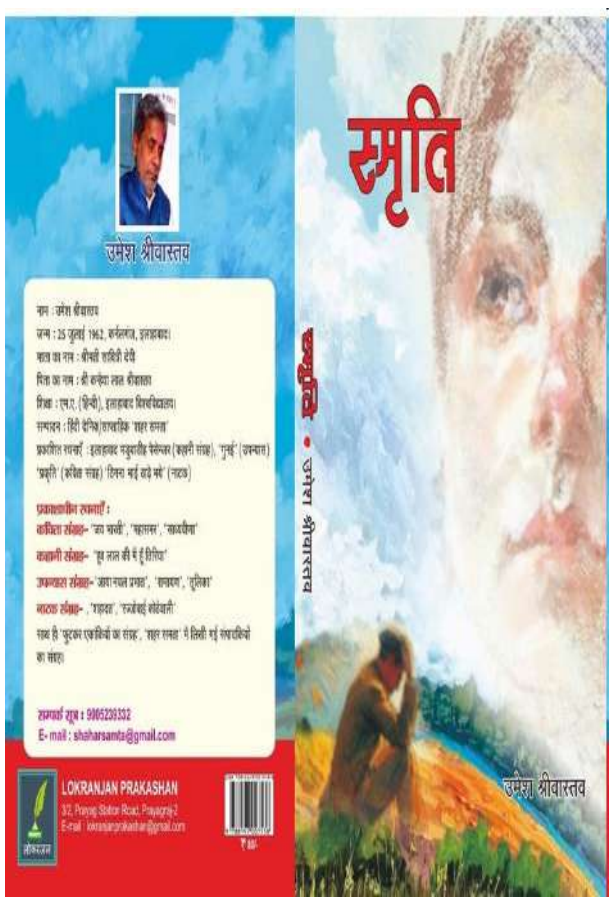

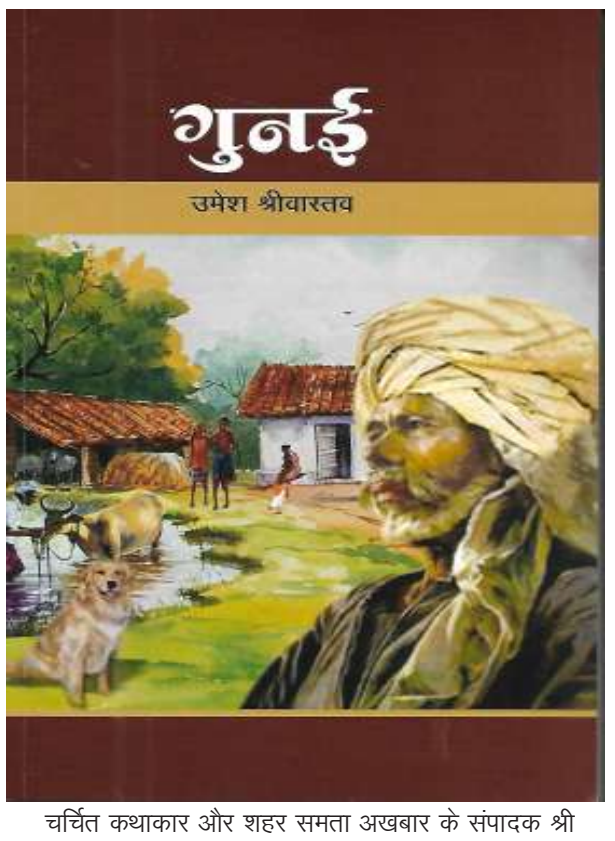

चर्चित कथाकार और शहर समता अखबार के संपादक श्री उमेश श्रीवास्तव जी का ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा बहु प्रतीक्षित

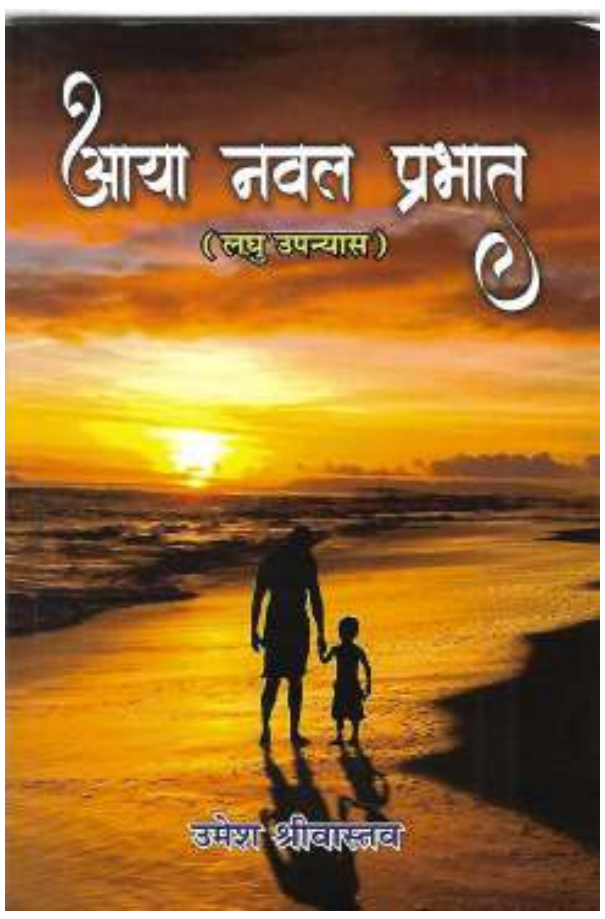

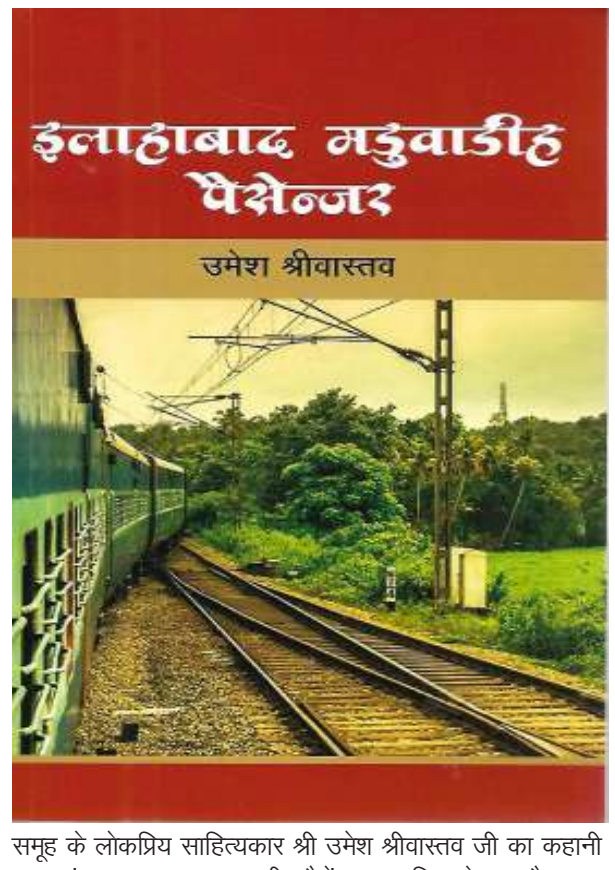

समूह के लोकप्रिय साहित्यकार श्री उमेश श्रीवास्तव जी का कहानी संग्रह इलाहाबाद मडुवाडीह पैसेंजर प्रकाशित हो गया है। उमेश श्रीवास्तव जी को बहुत बधाई एवम शुभकामना।

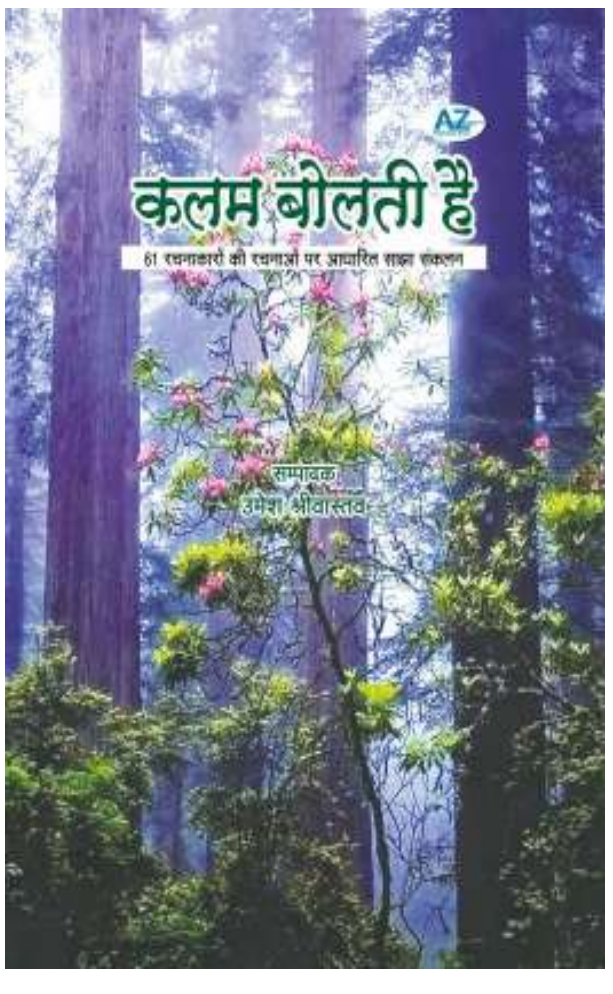

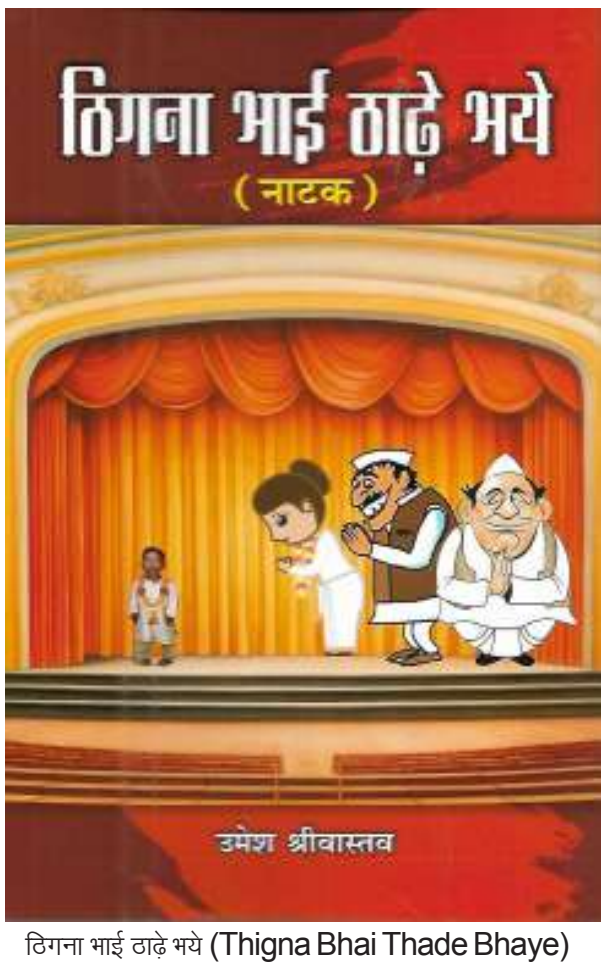

ठिगना भाई ठाढ़े भये (Thigna Bhai Thade Bhaye)

शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर एमईए के रुख के बाद भड़का बांग्लादेश, आईसीजे जाने की तैयारी

सत्ता से बेदखल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपने देश लौटने के इरादे की घोषणा के बाद, ढाका से तीखी प्रतिक्रियाएं आनी जारी हैं। गुरुवार तड़के राजधानी ढाका में हसीना के पूर्व डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी को दो अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, ऐसी खबरें भी हैं कि अगर भारत ने हसीना को प्रत्यर्पित नहीं किया, तो ढाका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटा सकता है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने भी दोहराया कि हसीना की वापसी की योजना को नाकाम कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा दिसंबर में सर्दियां आ जाएंगी, लेकिन कोई और नहीं आएगा। उन्होंने आगे कहा कि ढाका की योजना प्रत्यर्पण अधिनियम के तहत उन्हें



हथकड़ी पहनाकर वापस लाने की है। कबीर ने कहा भारत को भी अब अपनी जमीन पर एक श्आतंकवादीश को शरण देने की चुनौतियों और मुश्किलों का एहसास हो रहा होगा। अगर आप किसी को अपने घर बुलाते हैं और बाद में पता चलता है कि वह इतना अजीब बर्ताव कर रहा है और इतने आपत्तिजनक बयान दे रहा है कि आप उसे बाहर भी नहीं निकाल सकते और आपको उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो यह स्थिति एक बड़ी परेशानी बन जाती है। कबीर की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है, जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली, हसीना की देश वापसी और उनके प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश सरकार के अनुरोध को दो अलग–अलग मामलों के रूप में देख रही है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर का कहना है कि शेख हसीना बांग्लादेश और भारत के संबंधों में एक कांटा बन गई हैं और नयी दिल्ली को अब यह एहसास होने लगा है कि उनकी मौजूदगी से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा हो रहा है। समाचार पोर्टल 'बीडीन्यूज24' की खबर के अनुसार, कबीर ने भारत के संदर्भ में अपदस्थ प्रधानमंत्री हसीना की तुलना किसी ऐसे अनचाहे मेहमान से की, जो अचानक किसी के घर आ जाए। बांग्लादेश के मंत्री ने कहा कि भारत मुश्किल स्थिति में है, क्योंकि वह न तो हसीना को वहां से भेज सकता है और न ही उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर सकता है। उन्होंने बृहस्पतिवार को विदेश मंत्रालय में संवाददाताओं से कहा हसीना बांग्लादेश और भारत के संबंधों में एक कांटा बन गई हैं। वह एक परेशानी बन गई हैं और भारत समझ रहा है कि यह दोनों देशों के संबंधों के लिए एक समस्या है। कबीर की यह टिप्पणी भारत के उस रुख के एक दिन बाद आई है, जब उसने हसीना की 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटने की योजना पर टिप्पणी करने से परहेज किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को कहा था कि हसीना की स्वेच्छा से बांग्लादेश वापसी को ढाका के प्रत्यर्पण अनुरोध से अलग करके देखा जाना चाहिए।

इस्लामाबाद में रक्षा वार्ता : सऊदी अरब और तुर्किये संग साझा सुरक्षा पर बैठक करेगा पाकिस्तान

पाकिस्तान शुक्रवार को सऊदी अरब और तुर्किये के साथ उस त्रिपक्षीय रक्षा समझौते के तहत वार्ता की मेजबानी करने जा रहा है, जिसके तहत किसी एक सदस्य पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। दो सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इनमें यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब पर किए जा रहे हमले भी शामिल हैं। अधिकारियों ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर यह जानकारी दी, क्योंकि उन्हें बैठक के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करने की अनुमति नहीं थी। पाकिस्तान ने कहा है कि यह समझौता पूरी तरह रक्षात्मक प्रकृति का है और यह ईरान समेत किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। उसने कहा कि यह त्रिपक्षीय गठबंधन



रणनीतिक सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की साझा इच्छा को दर्शाता है। अधिकारियों के अनुसार, तीनों देशों के वरिष्ठ राजनयिकों के साथ–साथ रक्षा और सैन्य अधिकारियों के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। वे खतरों को रोकने, सैन्य सहयोग बढ़ाने, खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा उद्योग के बीच संबंध मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ, विदेश मंत्री इसहाक डार और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बैठक में शामिल होंगे। आसिफ ने कहा है कि हूती विद्रोहियों के हमलों से सऊदी अरब की रक्षा के लिए पाकिस्तान ''हर उपलब्ध साधन'' का इस्तेमाल करेगा। हालांकि, पाकिस्तान क्षेत्र में और उसके बाहर संघर्ष को बातचीत के जरिए समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान को फिर से वार्ता की मेज पर लाने के प्रयास कर रहा है। इस काम में वह कतर समेत पश्चिम एशिया के देशों की मदद ले रहा है। पाकिस्तान ने जून में दोनों पक्षों के बीच एक अंतरिम समझौता कराया था। शुक्रवार को होने वाली रणनीतिक, राजनीतिक और रक्षा समिति की बैठक संयुक्त मक्का रक्षा समझौते के तहत आयोजित की जा रही है। इस समझौते पर अगस्त में सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान सरकार ने बैठक से पहले इसकी विस्तृत जानकारी जारी नहीं की है। हालांकि, अधिकारियों ने सुरक्षा उपायों के तहत लोगों की आवाजाही सीमित करने के लिए इस्लामाबाद में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इस्लामाबाद यातायात पुलिस ने विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़क मार्गों में बदलाव की घोषणा की है और वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

आईआरजीसी की चेतावनी गोलीबारी के बाद बदला रास्ता, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पीछे हटा अमेरिकी एफ–16

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कहा है कि उसके एयरोस्पेस फोर्स ने होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) में हेंगाम द्वीप के दक्षिण–पूर्व में, एक अमेरिकी एफ–16 लड़ाकू विमान को ईरानी हवाई क्षेत्र से दूर



भगाने के लिए चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग द्वारा जारी एक बयान में, प्ल्ळ्ब एयरोस्पेस फोर्स के जनसंपर्क विभाग ने बताया कि अमेरिकी विमान तब ईरानी हवाई क्षेत्र के करीब आ गया था, जब वह जलमार्ग में षनियम तोड़ने वाले जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहा था और उन्हें हवाई सुरक्षा (एयर कवर) दे रहा था। आईआरजीसी के अनुसार, विमान को प्ल्ळ्ब एयरोस्पेस फोर्स की नई और उन्नत वायु रक्षा प्रणाली की ओर से चेतावनी के तौर पर की गई गोलीबारी का सामना करना पड़ा। इसके बाद पायलट को एक तेज पैंतरा अपनाना पड़ा, जिसके बाद उसने अपना रास्ता बदला और उस इलाके से पीछे हट गया। होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान के समुद्री यातायात नियमों को दरकिनार करने की कोशिशों के खिलाफ कड़ी चेतावनी देते हुए, प्ल्ळ्ब ने कहा कि ऐसी हरकतें जारी रखना स्वीकार्य नहीं है और ष्इससे नियमों का उल्लंघन करने वालों और उनका समर्थन करने वाले सैन्य बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्ल्ठ्ब की रिपोर्ट के अनुसार, इस बयान में अमेरिकी सैन्य कमांडरों को इस रणनीतिक जलमार्ग के पास बार–बार हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने को लेकर भी चेतावनी दी गई है।

आईआरजीसी के बयान में कहा गया स्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का हवाई क्षेत्र देश के सशस्त्र बलों के लिए एक श्रेड लाइनश (अंतिम सीमा) है। अगर अमेरिकी लड़ाकू विमान बार–बार इस हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें एक निर्णायक रक्षात्मक जवाब मिलेगा; एक ऐसा जवाब जिसका अंजाम वैसा ही हो सकता है, जैसा पहले निशाना बनाए गए थ–15 लड़ाकू विमान और अमेरिकी ड्रोनों का हुआ था।ष यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ईरान ने अपने सशस्त्र बलों की क्षमताओं के जरिए अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ने का संकल्प लिया है।

साइप्रस लेगा भारत से ब्रह्मोस, बौखलाए तुर्किए ने न्ठ को लिखी चिट्ठी

वैसे तो तुर्किए भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हरकतों और बयानबाजी में उसके साथ खड़ा दिखाई देता है। पाकिस्तान को समर्थन देता है। उसके साथ अपने सैन्य रिश्ते मजबूत करता है। लेकिन जब भारत और साइप्रस अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जब दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है तो उसी तुर्किए को इससे बड़ी परेशानी हो रही है। परेशानी इतनी तुर्किए टर्की ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का मामला सीधे संयुक्त राष्ट्र में उठा दिया है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल अब टर्की की चिंता का विषय बन गई है। तुर्किए ने यूएन को चिट्ठी लिखकर साइप्रस की बढ़ती सैन्य ताकत पर सवाल उठाए हैं और इस चिट्ठी में भारत और साइप्रस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की संभावित खरीद को लेकर हुई बातचीत का भी जिक्र किया है। दरअसल इस पूरी कहानी के पीछे साइप्रस का वो पुराना विवाद है जो दशकों से तुर्किए और ग्रीस के बीच तनाव की वजह बना हुआ है। 2 नवंबर 2026 को तुर्किए के संयुक्त राष्ट्र में स्थाई प्रतिनिधि अहमद यदि ने यूएन महासचिव को एक पत्र भेजा। इसके साथ उत्तरी साइप्रस के प्रतिनिधि का पत्र भी लगाया गया। इस चिट्ठी में टर्की ने दक्षिणी साइप्रस की बढ़ती सैन्य ताकत पर आपत्ति जताई। तुर्किए ने कहा कि साइप्रेस लगातार अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति दे रहा है। ग्रीस से 90 अपग्रेडेड लिपड टैंक मिलने की योजना है। इजराइल से मैकावा टैंक खरीदने पर बातचीत हो रही है और चार कैंटोस एंटी ड्रोन सिस्टम लेने में भी उसकी दिलचस्पी है। यह बात तुर्किए ने अपनी चिट्ठी में लिखी। लेकिन इस चिट्ठी में एक और बात लिखी गई। तुर्किए ने कहा कि मई 2026 में साइप्रस के राष्ट्रपति के भारत दौरे के बाद दोनों देशों के रणनीतिक रिश्ते मजबूत हुए और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की संभावित खरीद को लेकर व्यवस्थाएं होने की खबर हैं। चिट्ठी में मिसाइल की रेंज करीब 650 कि.मी. बताई गई है। यानी तुर्किए ने साइप्रस के हथियारों की खरीद की लिस्ट में भारत की ब्रह्मोस को भी शामिल कर दिया है।

भारत की ब्रह्मोस से तुर्किए को परेशानी किस बात की है?

इसका जवाब समझने के लिए भारत और साइप्रस के रिश्तों के साथ–साथ तुर्किए के पुराने विवाद को समझना होगा। दरअसल मई 2026 में साइप्रस के राष्ट्रपति भारत आए थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को राजनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया और रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 2026 से 2031 तक का रोड मैप भी तैयार किया गया। यानी भारत और साइप्रस अब सिर्फ सामान्य रिश्ते नहीं



रख रहे बल्कि रक्षा सहयोग भी बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और यही बात तुर्किए को परेशान कर रही है क्योंकि साइप्रस के साथ टर्की का पुराना विवाद है। साइप्रस और ग्रीस के साथ तुर्किए के रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। साइप्रस के बंटवारे के बाद से ही यह विवाद लगातार बना हुआ है। अब अगर इसे भारत पाकिस्तान के उदाहरण से समझा जाए तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। ऐसे में जब पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ता है तो तुर्किए अक्सर पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा दिखाई देता है। पाकिस्तान के साथ उसके सैन्य रिश्ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तुर्किए ने खुलेआम पाकिस्तान की मदद की थी। अब ठीक इसी तरह तुर्किए का विवाद साइप्स और ग्रीस के साथ है। ऐसे में अगर साइप्रस भारत के साथ अपने रक्षा संबंध मजबूत करता है तो तुर्किए को यह बात खटकती है क्योंकि भारत की ब्रह्मोस जैसी मिसाइल साइप्रस की सैन्य क्षमता बढ़ा सकती है।

संक्षिप्त

ईशनिंदा पर पंजाब विधानसभा सख्त : 298-A में उम्रकैद से भी कठोर कानून की मांग

पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा ने इस्लाम की सम्मानित हस्तियों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े अपराधों के लिए और कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है। प्रांतीय विधानसभा ने इस सप्ताह सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 298–ए के तहत निर्धारित सजा बढ़ाने के लिए कानून बनाने की मांग की। प्रस्ताव में कहा गया कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले अपराध के लिए मौजूदा सजा पर्याप्त नहीं है। फिलहाल धारा 298–ए के तहत कम से कम 10 साल की कैद का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास तक किया जा सकता है। विपक्षी दल पाकिस्तान तहरीक–ए–इंसाफ (पीटीआई) के विधायक राणा औरंगजेब ने यह प्रस्ताव पेश किया। इसमें कहा गया कि मौजूदा सजा पर्याप्त नहीं है। साथ ही संघीय सरकार से इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर उठाने और सजा बढ़ाने के लिए कानून लाने का आग्रह किया गया। सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली संघीय सरकार से धार्मिक पवित्रता की रक्षा तथा सामाजिक शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कानून बनाने और उसे लागू करने का आग्रह किया। अगस्त 2023 में संसद ने आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया था। इसमें धारा 298–ए के तहत सजा को तीन साल की कैद से बढ़ाकर कम से कम 10 साल करने का प्रस्ताव था। हालांकि, तत्कालीन राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए बिना इसे संसद को लौटा दिया था। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने प्रस्तावित संशोधन पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने चेतावनी दी है कि इससे आरोपियों के लिए वैधानिक जमानत हासिल करना और मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में जमानत कानूनी अधिकार के बजाय अदालतों के विवेक पर निर्भर हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन ने यह भी कहा है कि ईशनिंदा के मामले अक्सर कट्टरपंथी धार्मिक मौलवियों के दबाव में या निजी दुश्मनी निकालने के लिए शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्ज कराए जाते हैं। आयोग के अनुसार, ईशनिंदा के आरोपों के बाद भीड़ की हिंसा की आशंका को टालने के लिए पुलिस कभी–कभी कार्रवाई करती है।

ईयू बजट और यूक्रेन कर्ज पर वार्ता विफल, मैक्रों ने तय की साल के अंत की समयसीमा

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूरोपीय संघ (ईयू) के मुख्यालय में बृहस्पतिवार को बजट और अगले वर्ष यूक्रेन की आर्थिक एवं सैन्य आवश्यकताओं के लिए 49 अरब अमेरिकी डॉलर के नए ऋण को लेकर 12 घंटे से अधिक समय तक हुई वार्ता बेनतीजा रहने के बाद ईयू के अगले सात वर्षीय बजट पर समझौते के लिए साल के अंत तक की समयसीमा तय की है। वर्ष 2028–2034 के लिए प्रस्तावित यह बजट यूरोपीय संघ की व्यापक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। हालांकि, इसका आकार सदस्य देशों के राष्ट्रीय बजटों की तुलना में काफी छोटा है। इसका वित्तपोषण मुख्य रूप से 27 सदस्य देशों के योगदान से होता है, जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं के आकार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके यूरोपीय संघ की औसत सकल राष्ट्रीय आय के एक से 1.2 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है। ब्रसेल्स स्थित यूरोपीय संघ के मुख्यालय में बृहस्पतिवार को बजट और अगले वर्ष यूक्रेन की वार्ता हुई। हालांकि, इसके बावजूद नेता किसी आम सहमति पर नहीं पहुंच सके। मैक्रों ने तत्काल किसी समझौते की संभावना को खारिज कर दिया। फ्रांस इस समय भारी कर्ज के बोझ तले दबा है। देश में अप्रैल में चुनाव प्रस्तावित हैं, जिनमें दक्षिणपंथी कट्टरपंथी दलों की जीत की प्रबल संभावना जताई जा रही है। मैक्रों ने कहा कि जब यूरोपीय नेता 17–18 दिसंबर को दोबारा बैठक करेंगे, तब वह एक अच्छे समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि ''फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव बेहद करीब होने'' के कारण उनके लिए 31 दिसंबर के बाद ''बजट पर दोबारा चर्चा शुरू करना और उसे किसी नतीजे तक पहुंचाना संभव नहीं होगा।'' इससे पहले, हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मग्यार ने सोशल मीडिया पर कहा कि बृहस्पतिवार की बैठक ''पूरी तरह बेनतीजा'' रही और ''क्रिसमस तक भी किसी समझौते की उम्मीद नजर नहीं आती।''

ईरान के ड्रोन हमले का मलबा गिरने से कुवैत में 4 घायल, प्रतिष्ठान को नुकसान

कुवैत के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, गुरुवार को कुवैत में कम से कम चार लोग घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब ईरान के ड्रोन एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कुवैत की वायु रक्षा प्रणाली ने उन्हें रोक दिया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा ईरानी हमले में एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान को निशाना बनाया गया, जिसके कारण गिरे मलबे की चपेट में आने से चार लोग घायल हो गए।ष मंत्रालय ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। साथ ही, इस हमले से कुछ भौतिक नुकसान भी हुआ है, हालांकि इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। यह घटना कुवैत द्वारा ईरानी ड्रोनों को रोकने के लिए अपनी वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय करने के कुछ दिनों बाद हुई है।



प्रतापगढ़ ब्यूरो
शरद कुमार श्रीवास्तव
7/31, अचलपुर, प्रतापगढ़

संस्थापक
स्व.कन्हैया लाल
स्व.श्रीमती साधना
सम्पादक
उमेश चंद्र श्रीवास्तव
प्रबन्ध सम्पादक
अरविन्द पाण्डेय
संयुक्त सम्पादक
अनंत श्रीवास्तव
संयुक्त सम्पादक (तकनीकी)
केशव श्रीवास्तव
विधि सलाहकार
कल्पना श्रीवास्तव

शहर समता
स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक उमेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कम्पीटेन्ट बिजनेस सर्विसेज, विष्णु पदम कुटीर 115डी/2ई लूकरगंज, इलाहाबाद से मुद्रित कराकर 289/238ए,कर्नलगंज इलाहाबाद से प्रकाशित
सम्पादक
उमेश चन्द्र श्रीवास्तव
मो.नं.9005239332
आर.एन.आई.नं.
यूपीएचआईएन/2004/22466
Email : shaharsamta@gmail.com
इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के अधीन ही होंगे।